

पुलिस ने पटाखा कारोबारियों के साथ की बैठक: दुकानों में अग्निशमन यंत्र रखना जरूरी रास्तों पर कब्जा करने पर रोक, नियम तोड़े तो होगी कार्रवाई

छ.ग.फ्रंटलाइन
रायपुर। दीपावली पर पटाखा दुकानों में आग की घटनाएं रोकने और लोगों की सुरक्षा के लिए रायपुर पुलिस ने कारोबारियों को जरूरी निर्देश दिए हैं। दुकानों में अग्निशमन यंत्र रखना, पटाखों का तय सीमा में भंडारण करना और दुकानों के बीच निर्धारित दूरी बनाए रखना जरूरी होगा। दुकान के आसपास धूम्रपान, खुली आग और ज्वलनशील सामान रखने पर रोक रहेगी। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। गुरुवार को पुलिस कमिश्नरेट के पश्चिम और नॉर्थ जोन में पटाखा कारोबारियों की बैठक लेकर सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी दी गई। पश्चिम जोन की बैठक सिविल लाइन स्थित सी 4 भवन में हुई। इसमें ईगाहाभाठा मैदान में दुकान लगाने वाले कारोबारी भी शामिल हुए। वहीं, नॉर्थ जोन में



डीसीपी दीपमाला कश्यप की अध्यक्षता में अस्थायी पटाखा विक्रेताओं की बैठक हुई। पुलिस ने कारोबारियों को निर्देश दिए कि पटाखों की दुकानें केवल तय और अनुमति वाले स्थानों पर ही लगाई जाएं। दुकानों के बीच जरूरी दूरी रखी जाए और सड़क या आपातकालीन वाहनों के आने-जाने का रास्ता बाधित न हो। दुकानों के आसपास भीड़ जमा नहीं होने देने और बिजली की

व्यवस्था सुरक्षित रखने के लिए भी कहा गया है। पटाखों के भंडारण और बिक्री के दौरान सुरक्षा नियमों का पालन करना होगा। दुकानों में अग्निशमन यंत्र और दूसरे जरूरी सुरक्षा उपकरण उपलब्ध रखने होंगे। निर्धारित सीमा से अधिक पटाखे नहीं रखे जा सकेंगे। लाइसेंस की शर्तों का पालन करना भी अनिवार्य होगा।

संदिग्ध गतिविधि देखे तो पुलिस को दें सूचना
पुलिस ने कारोबारियों से कहा है



कि आग लगने की आशंका पैदा करने वाली गतिविधियों से बचें। किसी भी संदिग्ध गतिविधि या आपात स्थिति की जानकारी तत्काल पुलिस और संबंधित विभाग को दें। पश्चिम जोन की बैठक में अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त राहुल देव शर्मा ने सुरक्षा नियमों का गंभीरता से पालन करने की अपील की। वहीं, नॉर्थ जोन की डीसीपी दीपमाला कश्यप ने नियमों का उल्लंघन मिलने पर वैधानिक

कार्रवाई की चेतावनी दी।

साइबर ठगी से बचने के लिए भी किया जागरूक
बैठक के दौरान नॉर्थ जोन पुलिस ने 'साइबर पर संकल्प' अभियान के तहत पटाखा विक्रेताओं और मौजूद लोगों को ऑनलाइन ठगी से बचने की जानकारी दी। उन्हें अनजान लिंक पर क्लिक नहीं करने, फर्जी कॉल और मैसेज से सावधान रहने तथा बैंक खाते और निजी जानकारी किसी अनजान व्यक्ति से साझा नहीं

करने की समझाइश दी गई। पुलिस ने बताया कि साइबर ठगी होने पर राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।

दोनों जोन के अधिकारी रहे मौजूद
पश्चिम जोन की बैठक में सहायक पुलिस आयुक्त नवनीत पाटिल, आजाद चौक थाना प्रभारी अर्चना धुरंधर, अग्निशमन विभाग के निरीक्षक लीलेश्वर सिंह और नगर निगम के अधिकारी मौजूद रहे। वहीं, नॉर्थ जोन की बैठक में अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त आदित्य पांडे, एसपी उरला पूर्णिमा लामा, गुडियारी, खमतराई और उरला थाना प्रभारी, रामनगर चौकी प्रभारी तथा अस्थायी पटाखा विक्रेता शामिल हुए। पुलिस ने आम लोगों से भी अपील की है कि दीपावली पर पटाखों का सुरक्षित इस्तेमाल करें, सुक्ष्मा नियमों का पालन करें और साइबर अपराधों के प्रति सतर्क रहते हुए त्योहार मनाएं।

युवा प्रतिभाओं को मिलेगा मंच, बैकुंठपुर में 31 अक्टूबर को जिला स्तरीय युवा उत्सव

छ.ग.फ्रंटलाइन
कोरिया। छत्तीसगढ़ शासन के खेल एवं युवा कल्याण विभाग के निर्देशानुसार जिले की स्थानीय प्रतिभाओं को मंच प्रदान करने के लिए आगामी 31 अक्टूबर को जिला स्तरीय युवा उत्सव का आयोजन किया जाएगा। जिला मुख्यालय बैकुंठपुर के मानस भवन में आयोजित यह एक दिवसीय उत्सव प्रातः 9 बजे से प्रारंभ होगा। कलेक्टर श्रीमती रोहितमा यादव ने जिले के युवाओं से उत्सव में उत्साहपूर्वक भाग लेने और अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि युवा उत्सव युवाओं की रचनात्मकता, कला और सांस्कृतिक प्रतिभा को राष्ट्रीय पटल तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण मंच है। विकसित भारत चौलेंज ट्रैक के माध्यम से युवाओं को देश के समावेशी विकास के लिए अपने अभिनव विचार

साझा करने का अवसर भी मिलेगा। उत्सव में 15 से 29 वर्ष आयु वर्ग के युवा प्रतिभागी के रूप में भाग ले सकेंगे। संगतकारों के लिए आयु सीमा 18 से 40 वर्ष निर्धारित की गई है। आयु की गणना 17 अगस्त 2026 की स्थिति में की जाएगी। प्रत्येक प्रतिभागी किसी भी स्तर की प्रतियोगिता में केवल एक विधा में भाग ले सकेगा। खेल अधिकारी श्री जितेंद्र कुमार गुप्ता ने बताया कि आयोजन की सभी प्रशासनिक एवं व्यवस्थागत तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उत्सव में विकसित भारत चौलेंज ट्रैक सहित कला, साहित्य और संस्कृति से जुड़ी विभिन्न विधाओं में प्रतियोगिताएं होंगी। इनमें लोकगीत, चित्रकला, कविता लेखन और पारंपरिक वेशभूषा जैसी विधाएं शामिल हैं। रॉक बैंड प्रतियोगिता का आयोजन केवल राज्य स्तर पर किया जाएगा।

सुरक्षित बचपन अभियान के तहत विद्यार्थियों को पॉक्सो अधिनियम एवं बाल अधिकारों के प्रति किया जागरूक

मनेंद्रगढ़ के दो शासकीय विद्यालयों में हुई जागरूकता शिविर आयोजित, 664 छात्राओं ने लिया भाग

छ.ग.फ्रंटलाइन
मनेंद्रगढ़ (एमसीबी)। बच्चों की सुरक्षा, संरक्षण और अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से बचपन बचाओ आंदोलन के तहत 'सुरक्षित बचपन अभियान' अंतर्गत अखिल भारतीय विद्यालय जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया। इसके तहत मनेंद्रगढ़ के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय (ई. संवर्ग) एवं शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर विद्यार्थियों को लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (पॉक्सो अधिनियम), शिक्षा के अधिकार तथा बाल संरक्षण से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारीयें दी गईं। यह कार्यक्रम माननीय प्रधान जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव के निर्देशानुसार आयोजित किया गया। शिविर में जीएमएफसी भूमिका ध्रुव ने



विद्यार्थियों को बच्चों की सुरक्षा, उनके कानूनी अधिकारों और किसी भी प्रकार के शोषण से बचाव के संबंध में विस्तार से जानकारी दी।

पॉक्सो अधिनियम एवं बाल संरक्षण पर विशेष जोर
कार्यक्रम में विद्यार्थियों को पॉक्सो अधिनियम, 2012 के प्रावधानों और बच्चों को लैंगिक अपराधों से सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से अवगत कराया गया। उन्हें बताया गया कि प्रत्येक बच्चे को सुरक्षित वातावरण में रहने, शिक्षा प्राप्त

करने और सम्मान के साथ जीवन जीने का अधिकार है। बच्चों के प्रति किसी भी प्रकार के दुर्व्यवहार या शोषण की स्थिति में जागरूक रहना और उचित माध्यम से सहायता प्राप्त करना आवश्यक है।

शिक्षा का अधिकार और नैतिक मूल्यों की दी गई जानकारी
शिविर के दौरान शिक्षा के अधिकार, बाल संरक्षण और बच्चों के सर्वांगीण विकास से जुड़े विषयों पर चर्चा की गई। विद्यार्थियों को निष्ठा, ईमानदारी और जिम्मेदारी जैसे नैतिक



मूल्यों का महत्व समझाया गया। साथ ही उन्हें अपने अधिकारों के प्रति सजग रहने तथा किसी भी असुरक्षित परिस्थिति में विश्वसनीय व्यक्ति या संबंधित प्राधिकरण से सहायता लेने के लिए प्रेरित किया गया।

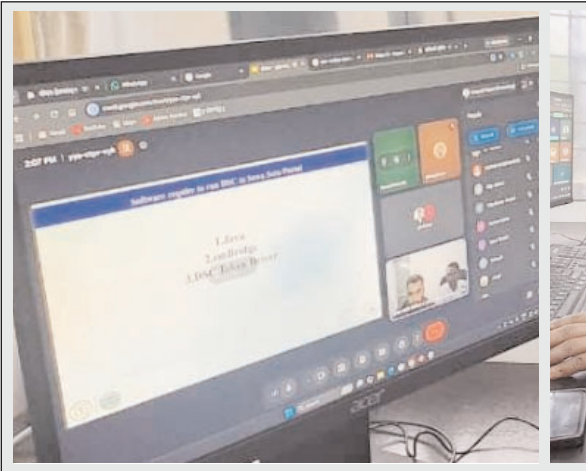
664 छात्राओं की रही सहभागिता
दोनों विद्यालयों में आयोजित जागरूकता कार्यक्रम में कुल 664 छात्राओं ने भाग लिया। इस अवसर पर विद्यालय की प्राचार्य अर्चना सहित विद्यालयीन स्टाफ की उपस्थिति रही। कार्यक्रम के

माध्यम से छात्राओं को सुरक्षित बचपन, शिक्षा, सम्मान और संरक्षण के प्रति जागरूक करने का प्रयास किया गया। कार्यक्रम में अधिकार मित्र (पीएलवी) अंजनी यादव की भी सहभागिता रही। 'सुरक्षा और संरक्षण हर बच्चे का अधिकार' संदेश के साथ आयोजित इस अभियान का उद्देश्य बच्चों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक बनाना तथा सुरक्षित एवं भयमुक्त वातावरण के निर्माण के लिए प्रेरित करना रहा।

सेवा सेतु पोर्टल से स्थानांतरण प्रमाण पत्र जारी करने हेतु प्राचार्यों को दिया गया ऑनलाइन प्रशिक्षण

प्रशिक्षण से विद्यालयों में टीसी जारी करने की प्रक्रिया होगी सरल, विद्यार्थियों एवं अभिभावकों को मिलेगी सुविधा

छ.ग.फ्रंटलाइन
मनेंद्रगढ़ (एमसीबी)। जिले में शैक्षणिक सेवाओं को डिजिटल, पारदर्शी एवं समयबद्ध बनाने की दिशा में आज सेवा सेतु पोर्टल के माध्यम से स्थानांतरण प्रमाण पत्र (टीसी) जारी करने संबंधी ऑनलाइन प्रशिक्षण आयोजित किया गया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित इस प्रशिक्षण में जिले के हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी स्कूलों के प्राचार्यों को पोर्टल के संचालन तथा स्थानांतरण प्रमाण पत्र जारी करने की ऑनलाइन प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य विद्यालय स्तर पर डिजिटल व्यवस्था का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना तथा विद्यार्थियों को स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्राप्त करने में होने वाली अनावश्यक परेशानियों को कम करना है। प्रशिक्षण कार्यक्रम में ई-जिला प्रबंधक श्री नारायण केवट एवं तकनीकी सहायक श्री



श्रवण कुमार लोधी द्वारा प्राचार्यों को सेवा सेतु पोर्टल के माध्यम से स्थानांतरण प्रमाण पत्र जारी करने की तकनीकी प्रक्रिया समझाई गई। इस दौरान पोर्टल के प्रभावी विद्यार्थियों की आवश्यक जानकारीयों की प्रविष्टि, विवरणों के सत्यापन तथा ऑनलाइन प्रमाण पत्र जारी करने से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं पर मार्गदर्शन दिया गया। प्रशिक्षण के माध्यम से प्राचार्यों को डिजिटल प्रणाली के

संचालन में दक्ष बनाने पर विशेष जोर दिया गया, ताकि विद्यालय स्तर पर प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया में तकनीकी त्रुटियों और अनावश्यक विलंब और संभावनाओं को कम किया जा सके। स्थानांतरण प्रमाण पत्र विद्यार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण शैक्षणिक दस्तावेज है, जिसकी आवश्यकता एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय में प्रवेश लेने के दौरान होती है। विशेषकर

शैक्षणिक सत्र के बीच विद्यालय परिवर्तन करने वाले विद्यार्थियों के लिए समय पर टीसी प्राप्त करना अत्यंत आवश्यक होता है। प्रमाण पत्र जारी होने में विलंब से विद्यार्थियों की प्रवेश प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। इसकी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए आयोजित प्रशिक्षण से विद्यालयों के प्राचार्य ऑनलाइन माध्यम से स्थानांतरण प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया को बेहतर ढंग से

समझ सकेंगे। इससे प्रमाण पत्र तैयार करने और जारी करने में लगने वाले समय को कम करने, दस्तावेजों की जानकारी व्यवस्थित रखने तथा विद्यार्थियों एवं अभिभावकों को समय पर सेवाएं उपलब्ध कराने में सहायता मिलेगी। विद्यालयीन कार्यों में बढ़ेगी पारदर्शिता और कार्यकुशलता सेवा सेतु पोर्टल के माध्यम से स्थानांतरण प्रमाण पत्र जारी करने की व्यवस्था से

विद्यालयीन प्रशासनिक कार्यों में डिजिटल तकनीक का उपयोग बढ़ेगा। ऑनलाइन प्रणाली से प्रमाण पत्र से संबंधित जानकारीयों का व्यवस्थित संधारण करने, अभिलेखों के प्रबंधन को सुगम बनाने तथा मानवीय त्रुटियों को कम करने में मदद मिलेगी। साथ ही प्राचार्यों को पोर्टल संचालन का प्रशिक्षण मिलने से तकनीकी समस्याओं के कारण कार्य प्रभावित होने की संभावना भी कम होगी। यह प्रशिक्षण केवल पोर्टल संचालन की जानकारी देने तक सीमित नहीं है, बल्कि विद्यालयों में डिजिटल कार्यप्रणाली को मजबूत बनाने की दिशा में भी महत्वपूर्ण पहल है। इससे विद्यार्थियों एवं अभिभावकों को शैक्षणिक सेवाओं का लाभ अधिक सरलता से उपलब्ध कराने तथा शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली को अधिक जवाबदेह, पारदर्शी एवं समयबद्ध बनाने में सहायता मिलेगी।

जिले में अब तक 1236.8 मिमी औसत वर्षा दर्ज

छ.ग.फ्रंटलाइन
मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी। मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले में 1 जून से 29 अक्टूबर 2026 तक 1236.8 मिमी औसत वर्षा दर्ज की गई है। कलेक्टर भू-अभिलेख शाखा से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस अवधि में कोटडोल तहसील में सर्वाधिक 1604.0 मिमी, जबकि खड़गावां में न्यूनतम 928.7 मिमी वर्षा रिकॉर्ड की गई। तहसीलवार वर्षा के आंकड़ों के अनुसार मनेन्द्रगढ़ में 1219.6 मिमी, चिरमिरी



में 1125.9 मिमी, केल्हारी में 994.8 मिमी, भरतपुर में 1548.0 मिमी तथा कोटडोल में 1604.0 मिमी वर्षा दर्ज हुई है।

दैनिक छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन
सत्य के प्रति समर्पित

एजेंसी / वितरक की आवश्यकता

दैनिक छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन को चिरमिरी, खड़गावां एवं भरतपुर क्षेत्रों के लिए एजेंट / वितरकों की आवश्यकता है।

इच्छुक व्यक्ति शीघ्र संपर्क करें।

संपर्क सूत्र: 7566950555

पता: दैनिक छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन, अंबिकापुर, जिला-सरगुजा (छत्तीसगढ़)

निरीक्षक ढाल सिंह साहू बनाए गए जयनगर थाना प्रभारी

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन बिश्रामपुर। पुलिस अधीक्षक योगेश कुमार पटेल ने जिले के आठ निरीक्षकों को नई जिम्मेदारी सौंपी है। इसके अतिरिक्त दो उपनिरीक्षक, आठ सहायक उपनिरीक्षक सहित अलग अलग थानों में पदस्थ पचपन आरक्षकों का तबादला कर उन्हें नए थाना चौकियों में पदस्थापित किया है गुरुवार को पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी आदेश में निरीक्षक रंजीत प्रताप सिंह रक्षित केंद्र से शिकायत शाखा प्रभारी पुलिस कार्यालय, निरीक्षक रमेश पटेल रक्षित केंद्र से थाना प्रभारी रामानुजनगर, निरीक्षक नंद किशोर गौतम रक्षित केंद्र से रीडर टू एसपी कार्यालय, निरीक्षक सत्यनायण देवांगन रक्षित केंद्र से थाना प्रभारी रमकोला, निरीक्षक मिलन सिंह रक्षित केंद्र से थाना प्रभारी चांदनी, निरीक्षक ढाल सिंह साहू रक्षित केंद्र से थाना प्रभारी जयनगर, निरीक्षक रूपेश कुंठल एक्का रक्षित केंद्र से प्रभारी साईबर सेल, निरीक्षक जावेद मियादाद को डीसीबी/डीसीआरबी/कंट्रोल रूम का प्रभारी बनाया गया है।उपनिरीक्षक अमित कुमार गुप्ता थाना प्रभारी जयनगर से चौकी प्रभारी बसदेई, उपनिरीक्षक हीरालाल साहू को थाना प्रभारी रमकोला से थाना सूरजपुर, अरुण गुप्ता को साईबर सेल से चौकी प्रभारी करंजी नियुक्त किया गया है। इसी प्रकार एसएसआई अमरेश सिंह रक्षित केंद्र से साईबर सेल, वरुण तिवारी को जयनगर, पास्कल लकड़ा को रक्षित केंद्र से थाना रामानुजनगर, बबिता यादव रक्षित केंद्र से थाना बिश्रामपुर, राकेश यादव को थाना प्रतापपुर, हरिशंकर तिवारी को बिश्रामपुर से थाना चंदौरा, सुनील भारती को चंदौरा से भटगांव पदस्थ किया गया है। आदेश में आधा दर्जन प्रधान आरक्षक के अलावा आरक्षकों को भी नई पोस्टिंग दी गई है।

चक्रवाती तूफान की बारिश ने किसानों की मेहनत पर फेरा पानी

खेतों में खड़ी फसल से लेकर खलिहानों में रखे धान तक पर मंडराया नुकसान का खतरा

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन बिश्रामपुर। चक्रवाती तूफान के प्रभाव से मौसम में आए अचानक बदलाव ने कोयलांचल सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में जनजीवन को प्रभावित कर दिया है। बुधवार दोपहर से शुरू हुई बारिश का सिलसिला गुरुवार को भी लगातार जारी रहने से किसानों की चिंता बढ़ गई है। खेतों में लहलहा रही धान की फसल से लेकर कटाई के बाद खलिहानों में रखे धान तक पर बारिश की मार पड़ रही है। वहीं सब्जी उत्पादन के लिए पहचाने जाने वाले सिलफिली और आसपास के गांवों में भी मौसम के बदले मिजाज से सब्जी की फसलों को नुकसान पहुंचने की खबर है। अचानक बदले मौसम ने किसानों की मेहनतों की मेहनत और लागत पर संकट खड़ा कर दिया है। यूं तो खेती-किसानी पूरी तरह मौसम पर निर्भर रहती है। किसान पूरे सीजन खेतों में पसीना बहाकर फसल तैयार करते हैं और जब उपज घर लाने का समय नजदीक आता है, तब मौसम की प्रतिकूलता उनकी मेहनत पर भारी पड़ने लगती है। कोयलांचल क्षेत्र में तेज हवाओं के साथ हो रही बारिश ने एक बार फिर किसानों के सामने इसी तरह की चुनौती खड़ी कर दी है। बुधवार दोपहर से आसमान में छाए बादलों और शुरू हुई

बारिश ने ग्रामीण इलाकों का सामान्य जनजीवन प्रभावित किया। गुरुवार को भी बारिश जारी रहने से किसानों की मुश्किलें कम होने के बजाय बढ़ती नजर आई। धान की फसल को लेकर किसानों की



चिंता स्वाभाविक है। खेतों में खड़ी फसल को सुरक्षित रखने के साथ कटाई के बाद उपज को सूखाकर भंडारित करना भी जरूरी होता है। ऐसे समय में लगातार बारिश होने से खेतों में मौजूद फसल और खुले में रखी उपज दोनों के प्रभावित होने की आशंका बढ़ जाती है। किसानों के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वे मौसम को इस अनिश्चितता के बीच अपनी मेहनत से तैयार उपज को आखिर किस तरह सुरक्षित रखें। धान की खेती करने वाले किसानों के लिए केवल खेतों में खड़ी फसल ही चिंता का कारण नहीं है, बल्कि खलिहानों में रखे धान की सुरक्षा भी बड़ी

समस्या बन गई है। कटाई के बाद खुले स्थानों पर रखी गई फसल बारिश के पानी से भीगने पर उसकी गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है। धान को पर्याप्त रूप से सुखाने और सुरक्षित रखने में परेशानी आने से किसानों को



अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ सकती है। यदि धान लंबे समय तक नमी की चपेट में रहता है, तो उसके खराब होने, रंग और गुणवत्ता प्रभावित होने तथा भंडारण के दौरान परेशानी बढ़ने का खतरा रहता है। इससे किसानों को उपज के उचित मूल्य को लेकर भी चिंता हो सकती है। हालांकि, क्षेत्र में धान की फसल को हुए वास्तविक नुकसान का आंकड़ा अभी सामने नहीं आया है, लेकिन लगातार बारिश ने किसानों की आशंकाएं जरूर बढ़ा दी हैं। खेतों में खड़ी धान की फसल के लिए लगातार बारिश और नमी की स्थिति नुकसानदायक साबित हो

सकती है। खेतों में पानी जमा होने की स्थिति बनने पर फसल प्रभावित होने का खतरा बढ़ जाता है। साथ ही बारिश के कारण कटाई और उपज को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाने में देरी हो सकती है। मौसम की



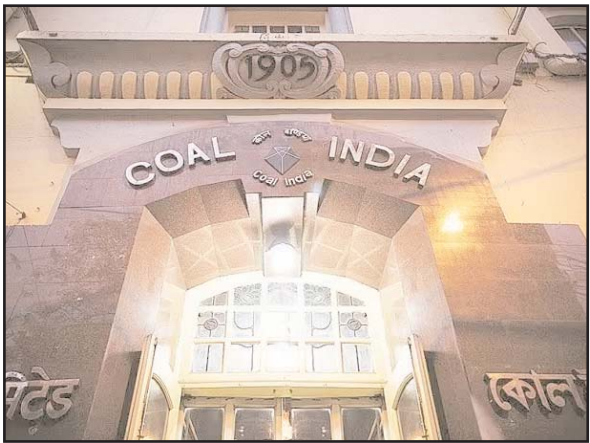
मार से उत्पादन प्रभावित होने की आशंका किसानों को भविष्य की आमदनी और घरेलू जरूरतों को लेकर भी परेशान कर रही है। सिलफिली की सब्जी खेती पर भी मौसम का असर

को नुकसान पहुंचने से किसानों की चिंता बढ़ गई है। सब्जी की खेती में अत्यधिक नमी और खेतों में पानी जमा होने से पौधों की जड़ों पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है। कुछ फसलों में रोग लगने की आशंका बढ़ जाती है,



बारिश के कारण उत्पादन या बाजार तक पहुंच प्रभावित होती है, तो इसका सीधा असर किसानों की रोजाना होने वाली आमदनी पर पड़ सकता है। फसल तैयार होने के बाद मौसम बिगड़ जाए, तो किसानों के सामने नुकसान की भरपाई की बड़ी चुनौती खड़ी हो जाती है। लगातार बारिश के बीच किसानों की नजर अब मौसम साफ होने और फसलों की वास्तविक स्थिति सामने आने पर टिकी है। खेतों में खड़ी फसल, खलिहानों में रखे धान और सब्जी की खेती को हुए नुकसान का आकलन होने के बाद ही प्रभावित किसानों की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

कोल इंडिया कर्मचारियों की एचआरए की दरों में हुई बढ़ोतरी



प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन बिश्रामपुर। कोल इंडिया के कर्मचारियों के लिए मकान किराया भत्ते को लेकर बड़ी राहत की खबर है। कोल इंडिया प्रबंधन ने एचआरए की दरों में बढ़ोतरी का आदेश जारी कर दिया है। संशोधित दरों के अनुसार अब एक्स श्रेणी के शहरों में मूल वेतन का 27 प्रतिशत, वाई श्रेणी में 18 प्रतिशत और जेड श्रेणी के शहरों में 9 प्रतिशत मकान किराया भत्ता मिलेगा। नई दरें 1 सितंबर 2026 से प्रभावी मानी जाएंगी।

इस संबंध में कोल इंडिया के मानव संसाधन विभाग ने 22 अक्टूबर को कार्यालय आदेश जारी किया है। इस निर्णय से कंपनी में कार्यरत उन कर्मचारियों को लाभ मिलेगा, जिन्हें नियमानुसार मकान किराया भत्ते की पात्रता है। ज्ञात हो कि एचआरए कर्मचारियों के वेतन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, जिसका उद्देश्य आवास संबंधी खर्चों में आर्थिक सहायता देना है। शहरों की श्रेणी के आधार पर भत्ते की दरें निर्धारित की गई हैं। नई व्यवस्था के तहत एक्स श्रेणी के शहरों में सबसे अधिक 27 प्रतिशत, वाई श्रेणी में 18 प्रतिशत और जेड श्रेणी

के शहरों में 9 प्रतिशत की दर से भत्ता देय होगा। इस बढ़ोतरी से पात्र कर्मचारियों की मासिक वेतन गणना में बदलाव होगा। हालांकि वास्तविक लाभ कर्मचारी के मूल वेतन, पदस्थापना स्थल की श्रेणी और लागू सेवा नियमों के आधार पर निर्धारित होगा। ज्ञात हो कि कोल इंडिया की विभिन्न अनुषंगी कंपनियों और कोयला क्षेत्रों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए इस आदेश का महत्व है। नई दरें प्रभावी तिथि से लागू होने के कारण कर्मचारी अपने वेतन विवरण में संशोधित एचआरए और नियमानुसार देय अंतर की जानकारी का इंतजार करेंगे। आदेश के क्रियान्वयन के दौरान संबंधित कार्यालयों द्वारा पात्रता और भुगतान संबंधी नियमों के अनुरूप वेतन निर्धारण किया जाएगा। एचआरए दरों में इस संशोधन से कर्मचारियों को आवासीय खर्चों के मद में अतिरिक्त आर्थिक सहायता मिलने की उम्मीद है। अब कर्मचारियों की निगाहें इस बात पर रहेंगी कि संशोधित दरों के अनुसार भुगतान और बकाया अंतर का समायोजन किस प्रकार किया जाता है।

मखाना की खेती से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रही धमतरी की महिलाएं

धमतरी, छ.ग. फ्रंटलाइन। धमतरी जिले में कृषि विविधीकरण और ग्रामीण आजीविका को मजबूत करने की दिशा में मखाना की खेती नई संभावनाएं पैदा कर रही है। तालाबों में मखाना उत्पादन को बढ़ावा देने की पहल अब परिणाम देने लगी है। इसी कड़ी में ग्राम छाती और डांडेसरा में महिला स्व-सहायता समूहों द्वारा 29 एकड़ क्षेत्र में उत्पादित मखाना का संग्रहण शुरू हो गया है। साथ ही, महिलाओं को मखाना के संग्रहण और संग्रहण-पश्चात प्रबंधन की वैज्ञानिक तकनीकों का प्रशिक्षण देने की तैयारी की जा रही है। इससे

साहू, श्री जितेन्द्र कुमार साहू, पंचगण, कृषि विज्ञान केंद्र की विशेषज्ञ श्रीमती दीपिका चंद्रवंशी, उप संचालक उद्यानिकी श्रीमती पूजा कश्यप



साहू, उद्यान विकास अधिकारी श्री राहुल साहू और ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी श्री नर्मदा प्रसाद भारती उपस्थित रहे। उप संचालक उद्यानिकी श्रीमती पूजा कश्यप साहू ने बताया कि महिला समूहों को कृषि विज्ञान केंद्र, धमतरी में आगामी दिनों में मखाना के संग्रहण-पश्चात प्रबंधन का प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण में उपज की उचित देखभाल, प्रसंस्करण और गुणवत्ता बनाए रखने की तकनीकों की जानकारी दी जाएगी, ताकि महिलाएं इस गतिविधि को आजीविका और उद्यमिता के रूप में आगे बढ़ा सकें। मखाना की कटाई मुख्य रूप से तीन चरणों में की जाती है। पहली कटाई को लहसर कहा जाता है। इसमें लगभग 70 प्रतिशत मखाना निकाल लिया जाता है। इस काम के लिए श्रमिकों को सामान्यतः प्रति किलोग्राम के आधार पर मजदूरी दी जाती है। इसके बाद

दूसरी और तीसरी कटाई मरकट और कर्कट कहलाती है। इन चरणों में बचे हुए लगभग 30 प्रतिशत बीज निकाले जाते हैं, जिसके लिए अधिक मेहनत

आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का माध्यम बन सकती है। इसके लिए उत्पादन के साथ वैज्ञानिक तकनीक, प्रसंस्करण, गुणवत्ता और बाजार से जुड़ाव

पर भी ध्यान देना जरूरी है। जिला प्रशासन का प्रयास है कि तकनीकी मार्गदर्शन और प्रशिक्षण के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं की भागीदारी बढ़े और वे आत्मनिर्भर आजीविका की दिशा में आगे बढ़ें। मखाना उत्पादन की यह पहल धमतरी जिले में पारंपरिक कृषि गतिविधियों के साथ नए विकल्प जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उचित प्रशिक्षण, गुणवत्ता आधारित प्रसंस्करण और

बाजार से बेहतर जुड़ाव मिलने पर यह पहल ग्रामीण महिलाओं के लिए रोजगार, स्वरोजगार और सामूहिक उद्यमिता के नए अवसर पैदा करने में सहायक होगी।



कार्यों को लेकर भी उन्होंने अनियमितताओं के आरोप लगाए। वर्मा ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं और कई जगहों पर कमीशनखोरी की शिकायतें सामने आ रही हैं। उन्होंने

आरोप लगाया कि सरकारी दफ्तरों में बिना कथित सुविधा शुल्क के काम कराना मुश्किल हो गया है। हालांकि, इन आरोपों के समर्थन में उन्होंने अपने बयान में विभागवार विस्तृत आंकड़े प्रस्तुत नहीं किए। सुरेंद्र वर्मा ने एसीबी और ईओडब्ल्यू के रिकॉर्ड का उल्लेख करते हुए सरकार से भ्रष्टाचार के मामलों पर जवाब मांगा। उन्होंने कहा कि सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि सरकारी विभागों में कथित रिश्तखोरी पर रोक लगाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि भ्रष्टाचार के मामलों में कार्रवाई सीमित स्तर तक रह जाती है, जबकि प्रभावशाली लोगों के खिलाफ पर्याप्त कार्रवाई नहीं होती। कांग्रेस प्रवक्ता ने प्रशासनिक व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ाने और आम नागरिकों की शिकायतों का त्वरित निराकरण सुनिश्चित

करने की मांग की। कांग्रेस नेता ने दावा किया कि पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान ऑनलाइन पोर्टल और प्रशासनिक प्रक्रियाओं के माध्यम से पारदर्शिता बढ़ाने के प्रयास किए गए थे। उन्होंने आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार के कार्यकाल में विचौलियों की भूमिका फिर बढ़ रही है। वर्मा ने कहा कि राजस्व, शिक्षा और पंचायत जैसे आम जनता से सीधे जुड़े विभागों में शिकायतों का प्रभावी निराकरण जरूरी है। उन्होंने राज्य सरकार से भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने, जवाबदेही तय करने और सरकारी सेवाओं को पारदर्शी बनाने की मांग की। नोट्स कांग्रेस के बयान में लगाए गए आरोप पार्टी के दावे हैं। एसीबी और ईओडब्ल्यू के आंकड़ों का विस्तृत विवरण तथा राज्य सरकार का इस संबंध में पक्ष उपलब्ध नहीं कराया गया है।

बिलासपुर में तालिबानी सजा, तोड़फोड़ के आरोपी को व्यापारी और गार्ड ने पीटा, पुलिस जांच में जुटी

बिलासपुर, (एजेंसी)। न्यायधानी बिलासपुर के तारबाहर थाना क्षेत्र अंतर्गत राजीव प्लाजा स्थित एक प्रसिद्ध डोसा दुकान में तोड़फोड़ और चोरी की कोशिश करने के आरोपी युवक की तालिबानी अंदाज में लाठी-डंडों व लात-चूँसों से बेरहमी से पिटाई का मामला सामने आया है। इस पूरी घटना का एक सनसनीखेज वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ लोग एक असहाय युवक को पीटते नजर आ रहे हैं और आसपास खड़े लोग मुकदर्शक बने हुए हैं। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस

प्रशासन हरकत में आ गया है और मारपीट में शामिल लोगों के खिलाफ जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, घटना सोमवार की बताई जा रही है। दुकान में तोड़फोड़ व चोरी का प्रयास राजीव प्लाजा स्थित डोसा दुकान में विक्री मानिकपुरी नामक युवक ने कथित तौर पर घुसकर तोड़फोड़ की और चोरी करने की कोशिश की। दुकान में तोड़फोड़ की भनक लगते ही वहां मौजूद व्यापारी और सुरक्षा गार्डों ने विक्री मानिकपुरी को रो हाथों पकड़ लिया। इसके बाद शाहन चंदा ने तारबाहर थाने में युवक के खिलाफ लिखित



शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर पुलिस ने युवक को वायरल हो गया। वायरल वीडियो में एक व्यक्ति युवक को लाठी-डंडों, लात और चूँसों से लगातार पीटा हुआ दिखाई दे रहा है,

को इस पूरी मारपीट का एक लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वायरल वीडियो में एक व्यक्ति युवक को लाठी-डंडों, लात और चूँसों से लगातार पीटा हुआ दिखाई दे रहा है,

जबकि अन्य सुरक्षार्कमी और लोग आसपास खड़े होकर तमाशा देख रहे हैं। सीएसपी गगन कुमार ने बताया कि वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए पुलिस ने निष्पक्ष जांच शुरू कर दी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि कानून हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं है। 27 अक्टूबर को सामने आए वीडियो के आधार पर मारपीट की परिस्थितियों और उसमें शामिल व्यापारी, गार्ड तथा अन्य लोगों की भूमिका की गहन जांच की जा रही है। साक्ष्यों के आधार पर मारपीट करने वालों पर भी वैधानिक कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

किसना ने छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में अपना एक्सक्लूसिव शोरूम खोला

राज्य में यह कंपनी का 7वां एक्सक्लूसिव शोरूम है

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

अंबिकापुर। किसना डायमंड एंड गोल्ड ज्वेलरी ने छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में, बनारस रोड पर अंबिका पेट्रोल पंप के पास अपने 7वें एक्सक्लूसिव शोरूम के भव्य उद्घाटन की घोषणा की। इस उद्घाटन समारोह में छत्तीसगढ़ सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव, पूर्व कैबिनेट मंत्री अजय अग्रवाल और हरि कृष्णा ग्रुप के संस्थापक घनश्याम ढोलकिया शामिल हुए। यह किसना के रिटेल विस्तार में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि है। हरि कृष्णा ग्रुप के संस्थापक घनश्याम ढोलकिया ने

कहा कि, ₹ अंबिकापुर में हमारी मौजूदगी, पूरे छत्तीसगढ़ में अधिक से अधिक ग्राहकों तक पहुंचने के किसना के संकल्प को और मजबूत करती है। राज्य में अपने 7वें एक्सक्लूसिव शोरूम के साथ, हम अपनी बेहतरीन डायमंड और गोल्ड ज्वेलरी के जरिए यहां के लोगों के त्योहारों और खास मौकों का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक हैं। यह विस्तार हमें हमारे 'हर घर किसना' के विजन के और करीब लाता है, जिसका उद्देश्य हर भारतीय परिवार तक डायमंड ज्वेलरी पहुंचाना है। किसना डायमंड एंड गोल्ड ज्वेलरी के सीईओ पराग शाह ने कहा,

दिवाली उपहार देने और ज्वेलरी खरीदने का एक अहम मौका है, ऐसे में हमें खुशी है कि हम अंबिकापुर के ग्राहकों के लिए किसना को लेकर आए हैं। हमारे विविध कलेक्शन और शानदार फेस्टिव ऑफर्स के जरिए, हम डायमंड और गोल्ड ज्वेलरी चुनने के अनुभव को और भी खास बनाना चाहते हैं - चाहे ग्राहक अपनी परंपराओं का जश्न मना रहे हों या जीवन की किसी नई शुरूआत का। किसना के एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट पार्टनर, राहुल गर्ग और कृष्णा अग्रवाल ने कहा, हमें अंबिकापुर में किसना को लाकर बहुत खुशी



हो रही है। हरि कृष्ण ग्रुप की विरासत और विशेषज्ञता वाले ब्रांड से जुड़ना हमारे लिए गर्व की बात है। हम अपने शोरूम में ग्राहकों का स्वागत करने के लिए तैयार हैं, जहां उन्हें डायमंड और गोल्ड ज्वेलरी



शानदार ऑफर लेकर आया है। इसमें डायमंड और सोने के आभूषणों की मेकिंग चार्ज (बनाने की लागत) पर 100% तक की छूट और केवल 25% डाउन पेमेंट पर 'डबल गोल्ड रेट प्रोटेक्शन' शामिल

90% बायबैक और 95% एक्सचेंज की सुविधा दे रहा है। साथ ही, ग्राहकों को 'ग्रेड लकी ड्रॉ' में हिस्सा लेने का मौका भी मिल रहा है, जिसमें वे कार या स्कूटर जीत सकते हैं। (नियम और शर्तें लागू)। समाज के प्रति अपनी ज़िम्मेदारी निभाते हुए, किसना ने लॉन्च के दौरान जरूरतमंद लोगों के लिए भोजन वितरण कार्यक्रम 'आयोजित किया। इस पहल में 'स्वच्छ भारत अभियान' के समर्थन में स्वच्छता अभियान, वृक्षारोपण अभियान और रक्तदान शिविर भी शामिल थे। ये गतिविधियाँ सामुदायिक कल्याण और पर्यावरण संरक्षण के प्रति किसना की प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं।

ग्राम खोखनिया में लगातार बारिश से धान की फसल पर संकट, किसान चिंतित

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

बलरामपुर। जिले के ग्राम खोखनिया में लगातार हो रही बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। 28 अक्टूबर से जारी बारिश के कारण धान की फसल को नुकसान की स्थिति बन गई है। खेतों में जलभराव से कटी और खड़ी दोनों तरह की फसल प्रभावित हो रही है।

कटाई के समय बारिश बनी आफत
इन दिनों धान की फसल कटाई के लिए पूरी तरह तैयार है। कई किसानों ने कटाई शुरू कर दी थी, तो कई जगह फसल खेत में ही खड़ी है। लगातार बारिश से खेतों में पानी भर गया है। इससे पकी

फसल के गिरने, दाने में अंकुरण आने और सड़ने की आशंका बढ़ गई है। हार्वैस्टर से कटाई भी नहीं हो पा रही है।

किसान शिवनारायण जायसवाल ने जताई चिंता
ग्राम खोखनिया के किसान शिवनारायण जायसवाल ने बताया कि इस बार फसल अच्छी थी, लेकिन ऐन कटाई के वक्त बारिश ने पूरी मेहनत पर पानी फेरने जैसी स्थिति बना दी है। उन्होंने कहा कि अगर 1-2 दिन और बारिश हुई तो धान की गुणवत्ता खराब हो जाएगी और समर्थन मूल्य पर बेचने में दिक्कत आएगी। खेत में गिरे धान को निकालने में मजदूरी खर्च भी बढ़ेगा।



चक्रवात अर्नब का असर
मौसम विभाग के अनुसार चक्रवात अर्नब के प्रभाव से उत्तर छत्तीसगढ़ सहित बलरामपुर जिले में बारिश की स्थिति बनी है। कृषि विभाग ने किसानों को सलाह दी है कि जहां तक संभव

हो कटी फसल को सुरक्षित स्थान पर ढक कर रखें और खेतों से पानी निकासी की व्यवस्था करें। किसानों ने प्रशासन से सर्वे कराकर नुकसान का आकलन करने और उचित मुआवजे की मांग की है।

स्पेशल कैपेन 6 में एसईसीएल ने लक्ष्य किया पार, स्क्रेप से 26.17 करोड़ की कमाई

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

बिलासपुर। साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एसईसीएल) ने केंद्र सरकार के स्पेशल कैपेन 6 में शानदार प्रदर्शन करते हुए नया लक्ष्यों को समय से पहले पार कर लिया है। स्वच्छता से लेकर स्क्रेप निपटान और रिकॉर्ड प्रबंधन तक हर मोर्चे पर कंपनी ने बढ़त हासिल की है।

226 स्थलों पर 47 लाख वर्गफुट में चला स्वच्छता अभियान

अभियान के तहत एसईसीएल ने 225 स्थलों पर सफाई का लक्ष्य रखा था, जिसके मुकाबले 226 स्थलों पर स्वच्छता गतिविधियां

संचालित की गईं। 40 लाख वर्गफुट सफाई के लक्ष्य के विरुद्ध 47 लाख वर्गफुट से अधिक क्षेत्र में सफाई की गई। इससे कार्यस्थल स्वच्छ और व्यवस्थित हुए हैं।
स्क्रेप निपटान से 26.17 करोड़ का राजस्व
एसईसीएल ने 3,300 मीट्रिक टन स्क्रेप निपटान के लक्ष्य के मुकाबले 4,602 मीट्रिक टन स्क्रेप का निपटान किया। इससे कंपनी को करीब 26.17 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ। यह संसाधनों के बेहतर उपयोग और कार्यस्थलों के प्रभावी प्रबंधन का उदाहरण है।

फाइल प्रबंधन में रिकॉर्ड तोड़ काम
भौतिक और इलेक्ट्रॉनिक



फाइलों के प्रबंधन में भी एसईसीएल ने लक्ष्य से कई गुना ज्यादा काम किया है। भौतिक फाइल समीक्षा: लक्ष्य 500, समीक्षा 2,100 फाइलों की भौतिक फाइल छंटनी: लक्ष्य 200, हटाई गई 872 फाइलें ई-फाइल समीक्षा: लक्ष्य

7,000, समीक्षा 14,215 ई-फाइलों की ई-फाइल बंद करना: लक्ष्य 3,000, निस्तारण 13,708 ई-फाइलों का इससे प्रशासनिक कामकाज तेज हुआ है और लंबित मामलों का निपटारा हुआ है।

वेस्ट टू वेल्थ पहल: कबाड़ से बनाई वेस्ट बिन

स्पेशल कैपेन 6 में ई-वेस्ट प्रबंधन पर विशेष जोर है। एसईसीएल मुख्यालय बिलासपुर में कर्मचारियों के पुराने इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जमा करने के लिए विशेष बिन लगाया गया है। खास बात यह है कि यह बिन भी अनुपयोगी सामग्री से बनाया गया है, जो 'वेस्ट टू वेल्थ' की अवधारणा को साकार करता है। विभिन्न क्षेत्रों में भी ई-वेस्ट संग्रहण अभियान चल रहा है। गौरतलब है कि स्पेशल कैपेन 6 का क्रियान्वयन चरण 2 से 31 अक्टूबर तक चल रहा है।

सरस्वती शिशु मंदिर में सुरक्षित बचपन जागरूकता कार्यक्रम, 250 विद्यार्थियों को दी बाल अधिकारों की जानकारी

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

अम्बिकापुर। बालिकाओं की सुरक्षा, शिक्षा और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत सरस्वती शिशु मंदिर, अंबिकापुर में ह्यसुरक्षित बचपन रूक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कलेक्टर अजीत वसंत के निर्देशन और जिला कार्यक्रम अधिकारी जे.आर. प्रधान के मार्गदर्शन में आयोजित कार्यक्रम में विद्यार्थियों को बाल अधिकारों, सुरक्षा कानूनों और हेल्पलाइन सेवाओं की विस्तृत जानकारी दी गई। कार्यक्रम में 250 से अधिक विद्यार्थी शामिल हुए।



पॉक्सो, साइबर सुरक्षा और बाल विवाह रोकथाम पर जानकारी

विधिक सेवा प्राधिकरण की नीलम बनसोडे ने बच्चों को कानूनी सहायता, नालसा की बाल हितैषी योजनाओं और हेल्पलाइन सेवाओं के बारे में बताया। विधिक सह परिवीक्षा अधिकारी सुमंती

खाखा ने पॉक्सो अधिनियम, बाल विवाह रोकथाम, साइबर सुरक्षा और स्पॉन्सरशिप योजना पर जानकारी दी। उन्होंने असुरक्षित परिस्थितियों की पहचान, साइबर अपराधों से बचाव और शोषण की स्थिति में सहायता लेने के तरीके बताए। मिशन शक्ति की जिला समन्वयक नूतन सिंह ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के उद्देश्यों,

बबिता यादव को विश्रामपुर, राकेश यादव को प्रतापपुर, हरिशंकर तिवारी को चंदौर और सुनील भारती को भटगांव भेजा गया है। बड़ी संख्या में रक्षित केंद्र से थानों में भेजा गया है। रामानुजपुर, सूरजपुर, प्रतापपुर, लटोरी, जयनगर, बसदेई, लटोरी, सलका-उमेश्वरपुर चौकियों में तैनाती बदली गई है। सुनील लकड़ा, हंसराम कर्नेडिया को रामानुजपुर, नवीन सिंह को यातायात, ममता केरेकेट्टा, रोशनी सिंह को सूरजपुर थाना, अंजना एक्का को बसदेई, प्रीति भगत को प्रतापपुर भेजा गया है।



शाखा प्रभारी, नंदकिशोर गौतम को रीडर टू एसपी, रूपेश कुंतल एक्का को साइबर सेल प्रभारी और जावेद मियांदाद को डीसीबी, डीसीआरबी और कंट्रोल रूम प्रभारी बनाया गया है। जयनगर टीआई अमित गुप्ता को बसदेई चौकी प्रभारी, रमकोला टीआई हीरालाल साहू को सूरजपुर थाना और साइबर सेल के एसआई अरुण गुप्ता को करंजी चौकी प्रभारी बनाया गया है। 7 एसआई की भी पदस्थापना बदली गई है। अमरेश सिंह को साइबर सेल, वरुण तिवारी को जयनगर, पास्कल लकड़ा को रामानुजपुर,

लुण्ड्रा विधायक ने 3.68 करोड़ के विकास कार्यों का किया भूमिपूजन

लमगांव में बनेगा उप स्वास्थ्य केंद्र, डडगांव-दोरना सड़क से ग्रामीणों को मिलेगी राहत

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

अम्बिकापुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में प्रदेश में अधोसंरचना विकास और बुनियादी सुविधाओं के विस्तार पर तेजी से काम हो रहा है। इसी कड़ी में सरगुजा जिले के लुण्ड्रा विकासखंड में आज दो अहम विकास कार्यों का भूमिपूजन हुआ। लुण्ड्रा विधायक प्रबोध भिंज ने ग्राम पंचायत लमगांव और डडगांव में कुल 3 करोड़ 68 लाख रुपए की लागत से स्वीकृत कार्यों का विधिवत पूजा-अर्चना कर भूमिपूजन किया। इन कार्यों के पूरा



होने से ग्रामीणों को स्वास्थ्य और सड़क सुविधा दोनों में बड़ी राहत मिलेगी।

लमगांव में 32 लाख से बनेगा नवीन उप स्वास्थ्य केंद्र

विधायक ने लमगांव में 32 लाख रुपए की लागत से बनने वाले उप स्वास्थ्य केंद्र भवन का भूमिपूजन किया। केंद्र बनने से

स्थानीय स्तर पर प्राथमिक उपचार, टीकाकरण, मातृ-शिशु स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होंगी। गर्भवती महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को अब छोटे इलाज के लिए लुण्ड्रा या अम्बिकापुर नहीं जाना पड़ेगा।

डडगांव से दोरना तक 3.36 करोड़ से 2 किमी सड़क

डडगांव से दोरना तक 2 किलोमीटर सड़क निर्माण के लिए 3.36 करोड़ रुपए स्वीकृत हैं। यह

सड़क डडगांव, दोरना सहित आसपास के कई गांवों को जोड़ेगी। बरसात में कीचड़ और आवागमन की दिक्कत खत्म होगी, किसानों को मंडी तक उपज ले जाने और बच्चों को स्कूल जाने में सुविधा होगी। विधायक प्रबोध भिंज ने कहा कि लुण्ड्रा क्षेत्र में स्वास्थ्य, शिक्षा और सड़क को प्राथमिकता दी जा रही है। सरकार का लक्ष्य गांव-गांव तक पक्की सड़क और स्वास्थ्य सुविधा पहुंचाना है। कार्यक्रम में जिला पंचायत उपाध्यक्ष देवनारायण यादव, विधायक प्रतिनिधि जयंत भिंज, लमगांव, दोरना, डडगांव के सरपंच, जनप्रतिनिधि, अधिकारी-कर्मचारी और बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे।

सिर्फ हंगामे की बजाय ठोस प्रमाण दे विपक्ष

लोकतंत्र में विरोध करना विपक्ष का अधिकार है, लेकिन हर विरोध को विश्वसनीय बनाने के लिए तथ्यों और प्रमाणों की कसौटी पर खरा उतरना भी जरूरी है। चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठाना जितना आसान है, उतना ही महत्वपूर्ण उन सवालों के पीछे ठोस आधार प्रस्तुत करना है। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर विपक्ष जिस तरह चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहा है, उसमें राजनीतिक आरोपों से आगे बढ़कर प्रमाणों के साथ अपना पक्ष रखने की जरूरत है। चुनावी सुधारों को संदेह के घेरे में खड़ा करना और पूरी व्यवस्था की निष्पक्षता पर सवाल उठाना गंभीर विषय है। यदि कहीं अनियमितता हुई है तो उसे तथ्यों के साथ उजागर किया जाना चाहिए, लेकिन आशंकाओं को ही आरोप और आरोपों को ही सब मान लेना लोकतांत्रिक विमर्श को कमजोर करता है। सुप्रीम कोर्ट में जारी सुनवाई में विपक्ष को अपने दावों की पुष्टि करने का अवसर दिया है। अब उसे सिर्फ हंगामे या शोर से नहीं, बल्कि ठोस प्रमाणों से अपनी बात साबित करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी और अन्य विपक्षी नेताओं की याचिका पर सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ताओं को चुनाव आयोग के हलफनामे का जवाब देने के लिए 10 दिन का समय दिया। अगली सुनवाई 17 नवंबर को निर्धारित की गई है। याचिकाकर्ताओं की ओर से बरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी कि आयोग ने एक दिन पहले ही अपना जवाब दाखिल किया है, इसलिए उसका अध्ययन करने के लिए समय चाहिए। इस पर मुख्य न्यायाधीश सर्वकांत ने कहा, 'हमें सब पता है। हम जांच करेंगे।' इस टिप्पणी से स्पष्ट है कि अदालत मामले को गंभीरता से सुन रही है। चुनाव आयोग ने अपने हलफनामे में एसआईआर से जुड़े फैसलों को तीनों चुनाव आयुक्तों की सर्वसम्मति से लिया गया बताया है। मुख्य चुनाव आयुक्त नानेश कुमार, चुनाव आयुक्त सुखवीर सिंह संघु और विवेक जोशी के हस्ताक्षर वाले हलफनामे में आयोग ने यह भी कहा कि फाइलों पर दर्ज सवाल, सुझाव या आपत्तियाँ अपने आप में अंतिम निर्णय के विरोध का प्रमाण नहीं हैं। आयोग के मुताबिक, एसआईआर के फॉर्म-6 में उसने कोई बदलाव नहीं किया है और नियमों के अनुसार उसमें संशोधन का अधिकार केंद्र सरकार के पास है। आयोग ने मतदाताओं की सुविधा और प्रक्रिया की निष्पक्षता से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण भी दिए हैं। जिन मतदाताओं के नाम का पुरानी मतदाता सूची से मिलान नहीं हो पाया है, उनके जरूरी दस्तावेज बीएलओ घर जाकर जुटा सकेंगे और ऑनलाइन अपलोड करेंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाने के संबंध में आयोग ने संवैधानिक प्रावधानों का हवाला देते हुए कहा कि इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने जैसी प्रक्रिया और आधार लागू होते हैं। दूसरी ओर, विपक्ष को भी यह बताना होगा कि उसकी आपत्तियाँ किन तथ्यों पर आधारित हैं, कहाँ नियमों का उल्लंघन हुआ है और किन मतदाताओं के अधिकार प्रभावित हुए हैं। केवल आशंका जताने या राजनीतिक आरोप लगाने से किसी दावे की पुष्टि नहीं होती। कुल मिलाकर मतदाता सूची का शुद्धिकरण लोकतंत्र की आवश्यकता है, लेकिन इस प्रक्रिया में किसी पात्र नागरिक का मताधिकार प्रभावित नहीं होना चाहिए। विपक्ष को समझना होगा कि केवल हंगामा करने से संदेह प्रमाण में नहीं बदलते। यदि अनियमितता हुई है तो उसके ठोस प्रमाण दें। सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए चुनावी व्यवस्था की विश्वसनीयता पर अनावश्यक चोट करने से बचें।

भाजपा बनाम कांग्रेस

डॉ. घनश्याम बादल



विचारधारा, मतभेद,

बदजुबानी और टकराव

लोकतंत्र में विचारों का टकराव स्वाभाविक है, लेकिन जब विचारों की जगह विद्वेष, तर्क की जगह तंज और राजनीतिक विरोध की जगह व्यक्तिगत चरित्रहत्यान ले ले, तब समझ लेना चाहिए कि राजनीति अपनी मर्यादा खो रही है। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच वैचारिक संघर्ष पुराना है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में यह संघर्ष जिस तरह कुटुता, अमर्यादित भाषा और संस्थाओं पर अविश्वास तक पहुंचा है, वह लोकतंत्र के स्वास्थ्य के लिए शुभ संकेत नहीं है। सवाल यह नहीं कि कौन-सा दल सही है और कौन गलत; सवाल यह है कि सत्ता और विपक्ष की लड़ाई में देश की सामाजिक एकता कहीं दांव पर तो नहीं लग रही? कांग्रेस और भाजपा दो अलग राजनीतिक धाराओं का प्रतिनिधित्व करती हैं। कांग्रेस की वैचारिक परंपरा स्वतंत्रता आंदोलन, धर्मनिरपेक्षता, बहुलतावाद, सामाजिक न्याय और विविधता में एकता की अवधारणा से जुड़ी रही है तो भाजपा की राजनीति सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, हिंदुत्व, राष्ट्रीय अस्मिता, मजबूत नेतृत्व और एकात्म मानववाद की वैचारिक धारा से प्रेरणा लेते हैं। इन दोनों विचारधाराओं के बीच मतभेद होना अस्वभाविक नहीं। लोकतंत्र में यही मतभेद विकल्प पैदा करते हैं मगर समस्या तब शुरू होती है, जब कोई दल अपनी विचारधारा को ही राष्ट्रभक्ति का प्रमाणपत्र बताने लगे और विरोधी विचारधारा को देश-विरोध का पर्याय बना दे। राष्ट्र कोई एक दल, विचार या नेता नहीं है।

कांग्रेस के समर्थक भी उतने ही भारतीय हैं, जितने भाजपा के समर्थक; और किसी दल का विरोध करना अपने आप में राष्ट्र का विरोध करना नहीं है। विडंबना यह है कि दोनों दल लोकतंत्र, संविधान और देशहित की दुहाई देते हैं, लेकिन उनके नेताओं की भाषा बार-बार इन्हीं मूल्यों पर चोट करती दिखाई देती है। सत्ता से सवाल पृथ्ना विपक्ष का धर्म है और विपक्ष की आलोचना का उत्तर देना सरकार की जिम्मेदारी। किंतु आलोचना और अपमान के बीच एक महीन रेखा है। उस रेखा को लांघते ही बहस का स्तर गिरता है और लोकतांत्रिक संवाद की जगह शत्रुता लेने लगती है। नेता भूल जाते हैं कि उनके शब्द केवल विरोधी दल तक सीमित नहीं रहते; वे समाज के व्यवहार, युवाओं की भाषा और आम नागरिकों की सोच को भी प्रभावित करते हैं। इसी कटु राजनीतिक वातावरण में एसआईआर यानी मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण जैसे मुद्दे टकराव का कारण बन रहे हैं। मतदाता सूची की शुद्धता चुनावी लोकतंत्र की बुनियादी आवश्यकता है। फर्जी, दोहराव वाले या अपात्र नामों को हटाना और पात्र मतदाताओं का नाम सुनिश्चित करना निर्वाचन प्रक्रिया की विश्वसनीयता के लिए जरूरी है। दूसरी ओर, यदि पुनरीक्षण की प्रक्रिया में किसी पात्र नागरिक का नाम छूटने, दस्तावेजों की कठिनाइयों या वास्तविक मतदाताओं के मताधिकार से वंचित होने की आशंका पैदा होती है, तो उस पर सवाल उठाना भी उतना ही आवश्यक है। इसलिए एसआईआर को केवल सरकार या निर्वाचन व्यवस्था के समर्थन-विरोध का प्रश्न बनाना उचित नहीं। प्रक्रिया पारदर्शी हो, पात्र मतदाताओं को पर्याप्त अवसर मिले, आपत्तियों का निष्पक्ष निस्तारण हो और गलतियों के सुधार की प्रभावी व्यवस्था हो-ये सभी पक्ष लोकतंत्र के हित में हैं। विपक्ष को बिना प्रमाण हर कार्रवाई को साजिश नहीं बताना चाहिए, तो निर्वाचन व्यवस्था को भी आलोचनाओं का उत्तर तथ्यों और पारदर्शिता से देना चाहिए। मताधिकार पर अविश्वास की स्थिति लोकतंत्र की जड़ों को कमजोर कर सकती है। एसआईआर के अतिरिक्त चुनावी निष्पक्षता, संवैधानिक संस्थाओं की भूमिका, आरक्षण, जातिगत गणना, धार्मिक पहचान, नागरिकता और केंद्र-राज्य संबंधों जैसे मुद्दों पर भी राजनीतिक खींचतान तीव्र हुई है। अंततः, कांग्रेस हो या भाजपा, दोनों को याद रखना चाहिए कि विचारधाराएं लोकतंत्र को दिशा देती हैं, जबकि अहंकार और बदजुबानी उसे कमजोर करते हैं। भारत की शक्ति उसकी विविधता, सहिष्णुता और संवाद की परंपरा में है। राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी को शत्रु मानने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाना समय की मांग है। देश की एकता और अखंडता केवल नारों से सुश्रुति नहीं रहती; उन्हें व्यवहार, भाषा और निर्णयों में भी उतारना पड़ता है। अस्तु, लोकतंत्र में लड़ाई विचारों की होनी चाहिए, व्यक्तिवों के अपमान की नहीं; नीतियों की होनी चाहिए, नागरिकों को बांटकर वोट झपटने की नहीं। सत्ता बदल सकती है, सरकारें आ-जा सकती हैं और विचारधाराओं के बीच संघर्ष चलता रह सकता है, लेकिन यदि इस संघर्ष में समाज का विश्वास, राष्ट्रीय एकता और संवैधानिक मर्यादा टूट जाए, तो जीत भले ही किसी किसी दल की नहीं हो जाए, पर, हार पूरे देश की होगी।

(लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं, वे उनके अपने विचार हैं।)

विचार

एआई आधारित साइबर अपराध की चुनौती



प्रो. (डॉ.) मनोज दयाल

शेयर बाजार की स्क्रीन पर हरा रंग...! उम्मीद जगता है...! पर उसी स्क्रीन के पीछे एक अदृश्य युद्ध भी चल रहा है। यह युद्ध टैकों का भी नहीं। मिसाइलों का भी नहीं। यह तो एल्गोरिदम का युद्ध है। कृत्रिम मेंधा ने जहां बाजार को तेज किया है, पारदर्शिता लाया है और समावेशी बनाया है। वहीं, इसी एआई ने साइबर अपराध को एक स्वचालित, बुद्धिमान और अजेय-सा हथियार भी दे दिया है। यही कारण है कि आज एआई आधारित साइबर अपराध, बैंक खाते की चोरी से कहीं आगे निकल कर, भारत के पूंजी बाजार की स्थिरता के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गया है। पूंजी बाजार के लिए अस्तित्व का खतरा मंडरा रहा है। बैंक में सेंध लगती है, तो एक ग्राहक प्रभावित होता है। बाजार में सेंध लगती है, तो 11 करोड़ डीमैट खाताधारकों का भरोसा डगमगा जाता है। एआई अपराध की यही मारक क्षमता इसे सबसे बड़ा खतरा बनाती है। कैसे करता है वार? पहला, डीपफेक मैनियूलेशन। मान लीजिए किसी दिग्गज कंपनी के सीईओ का डीपफेक वीडियो बनाकर यह फैला दिया जाए कि कंपनी के नतीजे खराब हैं। वरुद दिवालिया होने वाली है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल होते ही पैनिक सेलिंग शुरू हो जाएगी। निवेशक मिनटों में हजारों करोड़ गंवा देंगे। यह अब कल्पना नहीं...! 2024 में अमेरिकी बाजार में एक बड़ी कंपनी के साथ ऐसा प्रवास हो चुका है। दूसरा, हाइपर-पर्सनलाइज्ड फिशिंग। पहले फर्जी ईमेल की भाषा टूटी-फूटी होती थी। अब एआई आपके ट्रेडिंग व्यवहार, आपके ब्रोकर का नाम, आपके पोर्टफोलियो का विश्लेषण कर आपके ही ब्रोकर की भाषा में ईमेल बनाता है - 'आपका ट्रेडिंग अकाउंट वेरिफिकेशन के लिए रोका गया है। तुरंत इस लिंक पर केवाईसी करें।' एक क्लिक और आपका पासवर्ड, ओटीपी सब हैकर के पास। तीसरा, एल्गो-स्पाफिंग। एआई बॉट्स एक सेकंड में हजारों नकली खरीद-बिक्री के ऑर्डर लगाकर किसी शेयर की कीमत को कृत्रिम रूप से ऊपर-नीचे करते हैं। आपके स्टॉप-लॉस को ट्रिगर कराते हैं। आपको बाजार से बाहर कर अपना मुनाफा कमा लेते हैं। यह माइक्रो-सेकंड का लूटतंत्र है। इसे ही ईसानी ऑख पकड़ ही नहीं सकती। यही वजह है कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने अपनी ताकत रिपोर्ट में कहा है कि पूंजी बाजार अब केवल 'माकेट रिस्क' से नहीं, 'साइबर सिस्टमिक रिस्क' से भी जुड़ा रहा है। एनएसई की अति सराहनीय पहल है। एनएमआई के साथ मिलकर विशेष कार्यबल का अस्त्रान इस चुनौती को गंभीरता को समझते हुए नेशनल सैफ्टिफ़ेड एक्सचेंज (एनएसई) ने रक्षात्मक से आगे बढ़कर आक्रामक सुरक्षा की रणनीति अपनाई है।

जीवन-विकास का आधार सत्पुरुषार्थ

यदि व्यक्ति समुचित दिशा में समुचित पुरुषार्थ करता रहे तो जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता अर्जित की जा सकती है। जीवन में सफल होने के लिए पुरुषार्थ का महत्वपूर्ण स्थान है। पुरुषार्थ के अभाव में किसी भी उद्देश्य को पूर्ण नहीं किया जा सकता। पुरुषार्थ जीवन में हर समय अनिवार्य है। जीवन-विकास की आधारशिला पुरुषार्थ है, जो व्यक्ति अपने बुद्धि बल,



करंट अफेयर

डेमोक्रेटिक उम्मीदवारों का समर्थन कर सकते हैं ट्रंप समर्थक

अमेरिका में 2024 के राष्ट्रपति पद के चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप को वोट देने वाले कम से कम 25 प्रतिशत दक्षिण एशियाई अमेरिकी मतदाता तीन नवंबर को होने वाले मध्यावधि चुनावों में डेमोक्रेटिक उम्मीदवारों का समर्थन करने की योजना बना रहे हैं। एक सर्वेक्षण में यह जानकारी दी गई। लोगों के अधिकारों के लिए काम करने वाले स्पेन्डन 'इडियम अमेरिकन इम्यूव' द्वारा कराए गए इस सर्वेक्षण में जीवनयापन की लागत (65 प्रतिशत), स्वास्थ्य सेवा (53 प्रतिशत), रोजगार और वेतन (33 प्रतिशत) तथा शिक्षा (28 प्रतिशत) को मध्यावधि चुनावों के प्रमुख मुद्दों के रूप में पहचाना गया है। सर्वेक्षण में शामिल 800 पूंजीकृत दक्षिण एशियाई मतदाताओं में से 87 प्रतिशत भारतीय-अमेरिकी हैं जबकि शेष 13 प्रतिशत पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव, अफगानिस्तान और म्यांमा के अलावा कंबोडिया के खमेर समुदाय से संबंधित है। वर्ष 2024 के राष्ट्रपति चुनाव में कमला हैरिस को वोट देने वालों में से 96 प्रतिशत आगामी चुनावों में डेमोक्रेटिक उम्मीदवारों के पक्ष में अपना वोट डालने की योजना बना रहे हैं। सर्वेक्षण में पाया गया कि ट्रंप को वोट देने वाले 67 प्रतिशत दक्षिण एशियाई अमेरिकी अब भी रिपब्लिकन पार्टी का समर्थन करते हैं, लेकिन 25 प्रतिशत ने कहा कि वे डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवारों का समर्थन करेंगे।



एवं जानवरों के विकास की कड़ी को समझा जा सकता है, लेकिन जब वैज्ञानिकों को चमगादड़ों के जीवाश्म मिलते हैं, तो वे लगभग पूरी तरह विकसित चमगादड़ों के ही होते हैं। चमगादड़ उड़ान भरने और हवा में बने रहने के लिए राक्षस रूप से अपने पंखों का इस्तेमाल करने वाले इकलौते स्तनपायी हैं। पहले किए गए अध्ययनों में अमेरिका, अफ्रीका या एशिया को उनकी संभावित जन्मस्थली बताया गया था। अलग-अलग आंकड़ों और गणना के तरीकों से अलग-अलग नतीजे सामने आए।



इसलिए अब एक्सचेंज और ब्रोकर एक ही टीम के रूप में इस खतरे से लड़ेंगे। यह एक स्वागतयोग्य बदलाव है।यहां नियामक केवल दंड नहीं, बल्कि साझेदारी की बात कर रहा है। एक से तीन वर्ष का रोडमैप करने की कबिलेतारीफ पहल। हर सदस्य की तकनीकी जांच और सुरक्षा कवच। इस कार्यबल का सबसे व्यावहारिक और प्रभावी पहलू इसका समयबद्ध रोडमैप है। योजना के तहत सदस्यों का चरणबद्ध मार्गदर्शन किया जाने का प्रावधान है जिसका लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि अगले एक से तीन वर्षों में एएनएमआई के सभी सदस्यों को उचित साइबर मार्गदर्शन मिले, उनकी तकनीकी कमजोरियों की गहन जांच हो। उन्हें भविष्य के खतरों से सुरक्षित रखा जाए। यह कैसे संभव होगा? वर्ष 1 में ऑर्डर और जागरूकता का उद्देश्य है। सभी सदस्यों के सिस्टम का साइबर सिम्योरिटी ऑडिट, उनके कर्मचारियों के लिए डीपफेक और फिशिंग पहचान का प्रशिक्षण। छोटे शहरों के सब-ब्रोकर, जो अक्सर पुराने सॉफ्टवेयर पर काम करते हैं, उनकी पहचान और प्राथमिक सहायता। वर्ष 2 में अपग्रेडेशन और मानकीकरण पर बल देने की योजना है। कमजोर पाए गए

सिस्टम को अनिवार्य रूप से अपग्रेड करना, सभी टर्मिनलों पर मल्टी-फैक्टर ऑथेंटिकेशन और एंड-टू-एंड एंक्रिप्शन को अनिवार्य बनाना। ड्रिल, यानी नकली एआई हमला करके यह परखना कि ब्रोकर हाउस कितनी जल्दी रिकवर होता है। यह एक से तीन साल का यह 'सुरक्षा कवच' कार्यक्रम भारतीय पूंजी बाजार को केवल प्रतिक्रिया देने वाला नहीं, बल्कि भविष्य के लिए तैयार रहने वाला बाजार बनाएगा। सबसे आश्चर्य की बात... ! अमेरिका और जापान जैसे विकसित देश भी इससे अछूते नहीं हैं। यह तो वैश्विक महामारी बन चुका है। समाचारपत्रों, पत्रिकाओं व एआई पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार अमेरिका में 2024 में सिक्वोरिटिज एंड एक्सचेंज कमीशन के आधिकारिक 'एक्स' अकाउंट को हैक कर एआई-जनरेटेड पोस्ट से बिटकॉइन ईटीएफ की मंजूरी की झुठी खबर फैलाई गई, जिससे 5 मिनट में बिटकॉइन की कीमत 1,000 डॉलर उछल गई। एफबीआई के अनुसार, अमेरिका में वॉइस क्लोनिंग से सीईओ फ्रांझ के मामलों में पिछले साल 400% की वृद्धि हुई है। जापान में, टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज ने माना है कि उसके ब्रोकर सदस्यों पर एआई-आधारित डी-डॉस हमले बढ़े हैं, जहां बॉट्स नकली ट्रेडिफ़क से सिस्टम को जाम कर देते हैं ताकि उसी दौरान दूसरे रास्ते से सेंध लगाई जा सके। जब दुनिया के दो सबसे उन्नत तकनीक वाले बाजार भी इससे जूझ रहे हैं, तो भारत को और अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता है। यह लड़ाई वैश्विक है और इसका समाधान भी वैश्विक सहयोग से ही निकलेगा। भविष्य की ढाल क्रिप्टोग्राफीक सुरक्षा हो सकती है? साथ साथ क्वांटम तैयारी भी।

विशेषज्ञों का मानना है कि अगले 5 से 7 वर्षों में क्वांटम कंप्यूटर इतने शक्तिशाली हो जाएंगे कि वे मौजूदा एसएसएल ताले को सेकंड में तोड़ देंगे। तब आज का एंक्रिप्टेड डेटा भी असुरक्षित हो जाएगा। अतः यह निचोड़ निकाल सकते हैं कि एआई आधारित साइबर अपराध कौन कौन से तरीके आशंका नहीं, बल्कि हमारे ट्रेडिंग टर्मिनल के दरवाजे पर खड़ा एक वास्तविक खतरा है। एनएसई द्वारा एएनएमआई के साथ विशेष कार्यबल का गठन, एक से तीन साल का व्यावहारिक रोडमैप और क्वांटम-रेडी सुरक्षा की तैयारी - ये तीनों कदम बताते हैं कि भारत पूंजी बाजार इस खतरे को गंभीरता से ले रहा है। याद रखिए, बाजार में सबसे बड़ा मुनाफ़ा तेज ट्रेडिंग से नहीं, बल्कि सुरक्षित ट्रेडिंग से आता है। तकनीक के इस युग में निवेशक को सबसे बड़ी पूंजी उसका रिटर्न नहीं, उसकी सतर्कता है।

(लेखक कुलनाऊ करत विधि, रायपुर के कुलकर्णी हैं, वे उनके अपने विचार हैं।)

हनुमान जी से सीखें सफल होने के मंत्र

हिंदू धर्म में हनुमान जी को शक्ति, भक्ति, साहस और सेवा का प्रतीक माना जाता है। उनका जीवन केवल प्रभु श्रीराम के प्रति अटूट भक्ति की सीख नहीं देता, बल्कि मुश्किल समय में सही फैसला लेने, जिम्मेदारी निभाने और अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहने की प्रेरणा भी देता है। रामायण में हनुमान जी से



संकलित

प्रेरणा

जुड़ा। कई घंटा घंटाना ह, जा जावन का चुनातथा का सामना करने का रास्ता दिखाती है। उनके व्यक्तित्व के 8 गुण ऐसे हैं, जिनहें अपनाकर इंसान अपने काम और रिश्तों में बेहतर बखलाव ला सकता है। हनुमान जी का संवाद कौशल उनके व्यक्तित्व की बड़ी विशेषता था। अशोक वाटिका में माता सीता से मिलते समय उन्होंने अपनी वाणी और व्यवहार से उनका विश्वास जीता। इससे सीख मिलती है कि बात केवल अपनी बात रखने की नहीं, बल्कि सामने वाले की भावनाओं को समझने की भी है। सही शब्दों और विमन व्यवहार से कठिन बातचीत को भी आसान बनाया जा सकता है। समुद्र पार करते समय सुरसा ने हनुमान जी का रास्ता रोक लिया था। इस बाधा को उन्होंने केवल बल से नहीं, बल्कि अपनी बुद्धि और सूझबूझ से पार किया। उनका यह प्रसंग बताता है कि हर परेशानी का हटा ताकत दिखाने में नहीं होता है। कई बार शांत रहकर परिस्थिति को समझना और समय के अनुसार फैसला लेना ही सबसे बेहतर रास्ता होता है।



प्रकाश पर्व पर बधाई

सिद्ध धर्म के चौथे गुरु श्री रामदास के प्रकाश पर्व पर बधाई। उन्होंने अनुसूचर शहर की नींव रखी और दुनिया को आस्था का एक ऐसा चेहरा दिया, जो आज भी पूरी दुनिया को सेवा और मुक्ति का संदेश दे रहा है। -अनित शाह, वैदेशी गृहमंत्री



वोट चोरी

दिल्ली के हर व्यापारी से: हम आपसे प्यार करते हैं, आपकी बात सुन रहे हैं। मेरी सरकार ने बंद की, सड़के सरकार ने सील की, राजधानी पर ताला सरकार ने लगाया। जब वोट ही चोरी हो जाए, तो कुछ भी सुनिश्चित नहीं - न आपकी टुकान, न आपकी बचत, न आपके बच्चों का भविष्य। - राहुल गांधी, साहब, कांग्रेस

युवाओं के सपने

जिन युवाओं ने कभी देश की अजर्दी के लिए अपना खून बहया था, वे आज बेरोजगारी के कारण अपना खून बहाने को मजबूर हैं। बीजेपी ने युवाओं के सपनों को कुचल दिया है। यूपी इस समय बेरोजगारी और काम न मिलने के संकेत से गुजर रहा है। - अखिलेश यादव, साहब, राधा

जिंदगी की सच्चाई

जिंदगी की सच्चाई यह है कि जिन लोगों की आभ परभाव करते हैं, वे कभी न कभी आपको दुख पहुंचा देंगे। आपकी समझदारी इसी में है कि आप योग-समझदर तुने कि आभ किसे खुद को दुख पहुंचाने की इजाजत देते हैं। - रामगोपाल वर्मा, पिछलकर



खबर संक्षेप

आजम की 426 करोड़ की संपत्ति अटैच

प्रयागराज। प्रवर्तन निदेशालय के लखनऊ जोनल ऑफिस ने सपा के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री मोहम्मद आजम खान की रामपुर स्थित मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी की जमीन और इमारतों को अटैच करने की कार्रवाई की है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में अटैच की गई संपत्ति की कीमत 426.46 करोड़ रुपए आंकी गई है।

फिल्म महोत्सव की अंतिम तिथि बढ़ी

नई दिल्ली। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने 57वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 के लिए मॉडिया प्रत्यायन हेतु आवेदन करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 4 नवंबर कर दी है। सिनेमा की इस नई दुनिया का अनुभव करने के लिए प्रतिनिधि के रूप में पंजीकरण कर सकते हैं।प्रत्यायन पोर्टल से फार्म जमा कर सकते हैं।

ईशतहार

एतद् द्वारा आम ग्रामीण जन ग्राम अमादरहा, तहसील दरिमा, जिला सरगुजा छ०ग०, प.ह.नं. 7, रा.निम. - सोहगा को सूचित किया जाता है कि विक्रता सुशीला अग्रवाल पति धनराम दास अग्रवाल के द्वारा श्री विष्णु प्रसाद गोयल आ० स्व० श्री रामनिवास गोयल को 22 मार्च 2023 को विक्रय किया गया था को कार्यालय में पुस्तक क्रमांक आ.डी. 11294Ka-01 पेज नम्बर 334 359, S.No. 6359 में अंकित है। उक्त रजिस्टर्ड विक्रय पत्र की मूल प्रति जो सुशीला अग्रवाल ने बसंती पति विजयलाल अरजुन परमान से खरीदी थी जो 22 मार्च 2022 को विक्रय हुई थी की ऑरिजिनल कापी कही गुम हो गई है जिसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 27.10.2026 को मणीपुर थाना अम्बिकापुर में आवेदक ने दर्ज कराया है

एवं इस संबंध रपथ पत्र पी दिनांक 27.10.2026 को निष्पादित कराया गया है। यदि किसी जनसाधारण को उक्त रजिस्टर्ड विक्रय पत्र मिले है तो जल्द से जल्द आवेदक श्री विष्णु प्रसाद गोयल को लौटा देवे। आवेदक उक्त भूमि को बंधक रखकर बैंक से ऋण प्राप्त करना चाहता है। अतः उक्त रजिस्टर्ड विक्रय पत्र की वैधता का निराकरण एवं गुम होने के संबंध में किसी भी जनसाधारण को कोई आपत्ति हो तो वे स्वयं अथवा किसी विधिक प्रतिनिधि के माध्यम से 7 दिवस के भीतर बैंक में या आवेदक के समक्ष दावा आपत्ति पेश कर सकते है इसके पश्चात की गयी दावा आपत्ति मान्य नहीं होगी।

आवेदक

विष्णु प्रसाद गोयल

पता बिलासपुर चौक, कान्हा टायर्स आर.के. पेट्रोल पम्प के सामने अम्बिकापुर जिला सरगुजा छ०ग०

मो.नं. 9406132991

न्यायालय तहसीलदार अम्बिकापुर जिला-सरगुजा (छ०ग०)

रा०प०क्र०- /अ-6/2026-27

ईशतहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक सत्येन्द्र सिन्हा आ.स्व. सिद्धेश्वर प्रसाद सिन्हा निवासी फुन्दुरिडिहरी तहसील अम्बिकापुर जिला सरगुजा छ०ग० के द्वारा ग्राम फुन्दुरिडिहरी स्थित भूमि खसरा नंबर 130/37 रकबा 0.214 हे० भूमि राजस्व अभिलेखो से मृत खातेदार पार्वती देवी पति सिद्धेश्वर, अनुग्राह्य पिता सिद्धेश्वर, सरिता पिता सिद्धेश्वर, संगीता पिता सिद्धेश्वर एवं रोसनी सिन्हा पिता सिद्धेश्वर द्वारा अपने अपने हिस्से की भूमि को बिक्री पूर्व किये जाने का का नाम विलोपित करते हुये फौती नामांतरण दर्ज किये जाने हेतु आवेदन पेश किया गया है। उक्त संबंध में यदि किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई आपत्ति हो तो सुनवाई दिनांक 18.11.2026 के पूर्व स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि अथवा अधिपाक के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित होकर अपना दावा-आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। समय-सीमा के बाद प्राप्त दावा-आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। आज दिनांक:- 28/10/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालीन पदमुद्रा से जारी।

तहसीलदार

अम्बिकापुर, सरगुजा

चक्रवाती तूफान 'अर्नब' ने आंध्र प्रदेश और यानम में मचाई तबाही

आंध्र प्रदेश में 5 की मौत, 50 से ज्यादा ट्रेनें और उड़ानें रद्द, कई जगह पेड़ गिरे

तेज हवाओं और संभावित बाढ़ से निपटने के लिए उठाए जा रहे कदम

आंधी से उखड़े सैकड़ों पेड़-खंभे समुद्र में फंसा सल्फर से लदा मालवाहक जहाज

आंध्र प्रदेश के अंतर्वेदी के पास समुद्र में सल्फर ले जा रहा एक मालवाहक जहाज रास्ते से भटकने के बाद उथले पानी में फंस गया। यह घटना चक्रवात अर्नब के बीच सामने आई है। जहाज विशाखापत्तनम से रवाना हुआ था। बताया जा रहा है कि इंजन में खराबी आने के बाद जहाज अपना रास्ता भटक गया और अंततः अंतर्वेदी के पास समुद्र में फंस गया। संबंधित अधिकारियों के निरीक्षण के बाद जहाज की स्थिति का आकलन किया जाएगा और आगे की कार्रवाई तय की जाएगी।

यहां मारी बारिश से बाढ़ का भी खतरा मंडरा रहा

चक्रवाती तूफान 'अर्नब' ने बुधवार सुबह आंध्र प्रदेश और यानम के तटीय इलाकों में टकराना शुरू कर दिया है, जिससे वहां भारी बारिश हो रही है। भारी बारिश, तेज हवाओं और संभावित बाढ़ से निपटने के लिए आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में प्रशासन ने एहतियाती कदम तेज कर दिए हैं।मौसम विभाग ने कहा कि तूफान के केंद्र में हवा की रफ्तार 125 से 135 किमी प्रति घंटा है, जो झोंकों के साथ 150 किमी प्रति घंटा तक पहुंच रही है। पिछले तीन घंटों में तूफान 3 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से उत्तर-पश्चिम दिशा की ओर बढ़ा है। अनुमान है कि शुरुआत में धीमी गति से उत्तर-पश्चिम की तरफ बढ़ेगा और फिर उत्तर-उत्तर-पश्चिम की ओर रुख करेगा। बुधवार तड़के अर्णब आंध्र प्रदेश के तट के पास टकराया। इस पूरी प्रक्रिया में 6 घंटे से अधिक का समय लगा। चक्रवात से जुड़ी अलग-अलग घटनाओं में 5 लोगों की मौत हो गई।

मौसम विभाग ने मारी बारिश की चेतावनी दी

भुवनेश्वर स्थित क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र की निदेशक मंगेश्वरी ने बताया कि तूफान के जमीन की ओर बढ़ने के दौरान हवा की रफ्तार 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे रह सकती है। हवा के झोंकों की रफ्तार 80 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचने की आशंका है। मलकांगिरि, कोरापुट, नक्सलगपुर, रायगड़ा, गजपति और कालाहांडी में बेहद भारी बारिश और रेड अलर्ट जारी किया है।

रेल मंत्री रख रहे कटीबी नजर

रेल पटरियों पर 10 जगह गिरे पेड़, तेजी से हटाया गया

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी दी कि 'अर्नब' के टकराने के बाद रेलवे नेटवर्क पर 10 जगहों पर पेड़ गिर गए थे। राहत टीमों ने तत्परता दिखाते हुए सभी स्थानों से पेड़ों को तुरंत हटाकर ट्रक साफ कर दिया।

नायडू ने शाह से की बात

आंध्र प्रदेश के सीएमएन. चंद्रबाबु नायडू ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर 'अर्नब' से प्रभावित जिलों में एनडीआरएफ की टीमों की मदद बढ़ाने का अनुरोध किया है। केंद्र से अपील की है कि चक्रवाती तूफान से हुए जान-माल और फसलों के नुकसान का जायजा लेने के लिए केंद्रीय टीमों की जल्द से जल्द आंध्र प्रदेश भेजने को कहा है।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा

‘ब्रिग बैक बैलेट’ इंस्टा ब्लॉक केंद्र और मेटा से जवाब मांगा

एजेसी॥ नई दिल्ली

दिल्ली उच्च न्यायालय ने 'ब्रिग बैक

मद्रास हाईकोर्ट ने साफ की स्थिति

गैरहिंदुओं को नहीं मिलेगा मंदिर में प्रवेश, परंपरा से समझौता नहीं

एजेसी॥ चेन्नई

मद्रास हाई कोर्ट ने आगम मंदिरों में

मंत्रिमंडल ने कंटेनर विनिर्माण प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी

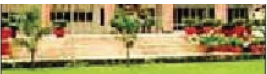
कंटेनर के आयात पर निर्भरता घटेगी व आपूर्ति मजबूत होगी

वैष्णव ने कहा-केंद्रीय बजट में की गई थी घोषणा

एजेसी॥ नई दिल्ली

योजना वित्त वर्ष 2039-

बैलेंट' नाम के इस्टाग्राम खात को ब्लॉक करने के खिलाफ दायर एक याचिका पर केंद्र सरकार और मेटा प्लेटफॉर्म से उनका पक्ष बताने को कहा है। इस्टाग्राम हैडल पर चुनावों में मत पत्र के इस्तेमाल का समर्थन करने वाली सामग्री प्रकाशित की जाती थी। न्यायमूर्ति अमित महाजन ने 27 अक्टूबर को अकाउंट संचालक, संगठन 'मिशन सेव कॉन्सिस्टेंस्यूशन' और इसके संस्थापक वकील महमूद प्राचा की



याचिका पर नोटिस जारी किया और 6 को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया। जिस दिन संगठन ने जंतर-मंतर पर 'ब्रिग बैक बैलेट'- ईवीएम हटाओ, देश बचाओ' नाम से एक शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करने का प्रस्ताव रखा, उसी दिन उसे पता चला कि भारत में उसका 'ब्रिग बैक बैलेट' हैडल उपलब्ध नहीं है।

बुंदेलखंड प्रयागराज के लोकप्रिय बाहुबली भाजपा नेता नहीं रोक सके मानसिंह यादव का रथ: सिद्धार्थ पांडे

संवाददाता

चित्रकूट। जनपद के समाजवादी पार्टी के युवा नेता जिला पंचायत सदस्य सिद्धार्थ पांडे ने बताया की मोदी योगी के

लोकप्रियता प्रजातंत्र में घट रही है। एम एल सी चुनाव में समाजवादी पार्टी के मानसिंह यादव ने बुंदेलखंड प्रयागराज स्नातक क्षेत्र से विजय हासिल कर लिया। बुंदेलखंड प्रयागराज में समाजवादी पार्टी का

जीत का रथ नहीं रोक पाए भाजपा के लोकप्रिय बाहुबली पदाधिकारी। कहा जाता है कि मऊ मानिकपुर के वर्तमान विधायक प्रयागराज, कौशांबी, चित्रकूट में बांदा में अपना दम



को सख्ती से लागू करने और नियमों के उल्लंघन के लिए जवाबदेही तय करने की मांग की गई थी। न्यायमूर्ति श्रीआर स्वामीनाथन और न्यायमूर्ति पी मुरगन की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि यह फैसला केवल आगम मंदिरों पर लागू होता है। आगम मंदिर प्राचीन ग्रंथों के अनुसार बनाया जाता है, प्रतिष्ठित किया जाता है।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को देश में वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी कंटेनर विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र तैयार करने के लिए 10,000 करोड़ के आवंटन वाली 'कंटेनर विनिर्माण प्रोत्साहन योजना' को मंजूरी दी। यह योजना वित्त वर्ष 2039-40 तक लागू रहेगी। योजना का उद्देश्य कंटेनर के आयात पर निर्भरता कम करना और आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करना है। इसके तहत नई

चित्रकूट पुलिस ने गैंगरेप की घटना में शामिल 50 हजार रुपए के इनामिया अभियुक्त को असलहा सहित किया गिरफ्तार

संवाददाता

चित्रकूट पुलिस अधीक्षक चित्रकूट अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में अपर



मानिकपुर चले गए। इसी दौरान साथी मौके से भागने में सफल रहा। वापस आने पर अभियुक्तगण पीड़िता को करीब 3-4 घंटे जंगल में रोकने के बाद उसके साथी की मोटरसाइकिल पर बैठकर मारकुंडी, हनुमानधारा होते हुए कबीं पेट्रोल पंप के पास छोड़ दिया और जान से मारने की धमकी देकर किसी को न बताने को कहा था। इस सूचना के आधार पर थाना मानिकपुर पर मु0अ0सं0 101/2026 धारा 70(2),127(2),351(3),304(2),131बीएनएस व 534/6 पॉक्सो एक्ट बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया। पुलिस अधीक्षक द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों के क्रम में घटना में शामिल अभियुक्त कोतवाली देहात जनपद बांदा(25 हजार का इनामिया) को पूर्व में गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। घटना में शामिल फरार अभियुक्त सुभाष उर्फ लल्लू उर्फ लाला पुत्र जगजीत वर्मा निवासी करवई थाना कोतवाली देहात जनपद बांदा को गिरफ्तारी हेतु पुलिस उपमहानिरीक्षक परिक्षेत्र,बांदा द्वारा 50 हजार रुपए का इनाम घोषित किया गया। इसी क्रम में दिनांक 27.10.2026 को प्रभारी निरीक्षक मानिकपुर व रडब्लू की संयुक्त टीम ने मुखबिर

40 तक लागू रहेगी सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा मंत्रिमंडल की बैठक में कंटेनर विनिर्माण प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी गई है। यह योजना 2039-40 तक लागू रहेगी। योजना के तहत पात्र विनिर्माताओं को ब्याज सस्मिडी, परिचालन व्यय सहयता, परिक्षण प्रमाणन सहयता तथा भूमि पट्टे पर लेने के लिए सहयता दी जाएगी।

की सूचना पर घटना में शामिल फरार इनामिया अभियुक्त सुभाष उर्फ लल्लू उर्फ लाला की तलाश में रवाना होकर झरी फाटक पर मौजूद थे कि मुखबिर ने आकर बताया कि वही इनामिया अभियुक्त चोरी की मोटरसाइकिल के साथ चूल्ही जाने वाले मोड़ के आस पास कोई घटना करने के फिराक में जंगल क्षेत्र में घूम रहा है जल्दी किया जाए तो पकड़ा जा सकता है। इस सूचना पर पुलिस टीम द्वारा घेराबंदी कर मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति को आवश्यक बल प्रयोग कर उसे पकड़ा गया। जिससे नाम पता पृछने पर अपना नाम सुभाष उर्फ लल्लू उर्फ लाला पुत्र जगजीत वर्मा निवासी करवई थाना कोतवाली देहात जनपद बांदा बताया जिसकी जामा तलाशी से 01 अदद एंड्रॉयड फोन वीवी,01 आधार कार्ड व 140 रुपये बरामद हुए तथा उसके पास मिली बिना नंबर की पल्सर मोटरसाइकिल जिसको ई-चालान से चेक करने पर उसका असली नंबर वड96व1482 होना पाया गया जो थाना मानिकपुर के मु0अ0सं0 177/26 धारा 303(2) बीएनएस की चोरी की है

बस्तर संभाग के 116 नेताओं की वीआईपी सुरक्षा में कटौती, केदार कश्यप-दीपक बैज शामिल: डिप्टी सीएम शर्मा

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

रायपुर। छत्तीसगढ़ में नक्सल हालातमें सुधार के बीच सरकार ने वीआईपी सुरक्षा की समीक्षा करते हुए बड़ा फैसला लिया है। बस्तर संभाग के भाजपा-कांग्रेस के 116 नेताओं की सुरक्षा श्रेणी कम करने की तैयारी है। इनमें कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप, पीसीसी चीफ दीपक बैज, पूर्व मंत्री महेश गागड़ा और कवासी लखमा शामिल हैं। 9 नेताओं की सुरक्षा जेड+ से घटाकर जेड की जाएगी। गृह विभाग जल्द औपचारिक आदेश



जारी करेगा।

डिप्टी सीएम विजय शर्मा का बयान

उपमुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि

परिस्थितियां सामान्य होने पर सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा होनी चाहिए। नेताओं को लोकसेवक बताते हुए विशेष सुरक्षा का नए सिरे से आकलन जरूरी है। इसे

पुलिस बल और संसाधनों के बेहतर उपयोग की दिशा में बदलाव माना जा रहा है।

किनकी सुरक्षा घटेगी

जानकारी के अनुसार केदार कश्यप, महेश गागड़ा, दीपक बैज, कवासी लखमा और कर्मा परिवार की जेड+ सुरक्षा घटाकर जेड की जाएगी। बाकी विधायकों, सांसदों और पूर्व मंत्रियों में कुछ की सुरक्षा जेड से वाई की जाएगी। अंतिम सूची गृह विभाग के आदेश से स्पष्ट होगी।

पर्यावरण संरक्षण में स्काउट्स-गाइड्स निभाएं भूमिका: राज्यपाल

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

लोकभवन में 1122 को दिया राज्य पुरस्कार

रायपुर। राज्यपाल रमेन डेका ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण आज सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। जल और जंगल बचाने के लिए सामूहिक प्रयास जरूरी हैं। स्काउट्स-गाइड्स जल संचयन और वनों की रक्षा में अहम भूमिका निभा सकते हैं। उन्होंने 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान की सराहना भी की। राज्यपाल लोकभवन के छत्तीसगढ़ मंडप में भारत स्काउट्स एवं गाइड्स द्वारा आयोजित राज्य पुरस्कार अलंकरण समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने प्रदेशभर के 1122 स्काउट्स, गाइड्स, रोवर्स और रेंजर्स को राज्य पुरस्कार प्रदान किए। अध्यक्षता शिक्षा मंत्री और



संगठन के प्रदेश अध्यक्ष गजेंद्र यादव ने की।

बस्तर में शांति के बाद विकास तेज - राज्यपाल

राज्यपाल ने कहा कि स्काउट्स का आदर्श वाक्य 'तैयार रहो' जिम्मेदारियों के

लिए तत्पर रहने की प्रेरणा देता है। पुरस्कार के साथ जिम्मेदारी भी बढ़ती है। बस्तर से आए स्काउट्स-गाइड्स की मौजूदगी पर उन्होंने खुशी जताते हुए कहा कि नक्सलवाद के ख़ात्मे के बाद बस्तर में शांति स्थापित

हुई है और क्षेत्र तेजी से विकास कर रहा है। शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने कहा कि स्काउटिंग की वर्दी अनुशासन, सेवा और समर्पण का प्रतीक है और स्काउटिंग से जुड़ा व्यक्ति जीवनभर सेवा भाव से काम करता है।

25 हजार की रिश्वत के आरोप में पटवारी निलंबित, 7 दिन में आरोप पत्र के निर्देश

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

बिलासपुर। राजस्व कार्य के लिए 25 हजार रुपए रिश्वत लेने के आरोप में कलेक्टर संजय अग्रवाल ने पटवारी ऋषिपुरी गोस्वामी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो की जांच में आरोप प्रथम दृष्टया सही पाए जाने के बाद यह कार्रवाई की गई। पटवारी पहले हल्का नंबर 14 में पदस्थ था, वर्तमान में पचपेड़ी तहसील के हल्का नंबर 05 में कार्यरत था। तहसीलदार पचपेड़ी ने 28 अक्टूबर को जांच रिपोर्ट सौंपी थी। आदेश में इसे छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियमों के



विरुद्ध गंभीर कदाचरण और शासन की छवि धूमिल करने वाला कृत्य बताया गया है।

जमीन बंटवारे के लिए 50

हजार में सौदे का दावा

मामला जमीन बंटवारे से जुड़ा है। वायरल वीडियो करीब 4 महीने पुराना बताया जा रहा है।

वीडियो सामने आने के बाद मस्तूरी एसडीएम बजरंग वर्मा ने तहसीलदार प्रकाश साहू को जांच सौंपी थी। पटवारी को बयान के लिए मस्तूरी बुलाया गया, लेकिन वह नहीं आया। वीडियो में पटवारी जमीन मालिकों से पैसों के लेनदेन की बात करता दिख रहा है। दावा है कि बंटवारे के लिए 50 हजार

रुपए में सौदा तय हुआ था, जिसमें 25 हजार रुपए पटवारी के हिस्से थे। वीडियो में एक व्यक्ति नोटों की गड्ढी देता दिख रहा है और पटवारी कहता है कि इतनी रकम से काम नहीं चलेगा।

निलंबन में कोटा रहेगा मुख्यालय

निलंबन अवधि में पटवारी का मुख्यालय एसडीएम कोटा कार्यालय में रहेगा और नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता मिलेगा। कलेक्टर ने तहसीलदार पचपेड़ी को 7 दिन में आरोप पत्र तैयार करने के निर्देश दिए हैं। अंतिम निष्कर्ष विभागीय जांच के बाद आएगा।

राजधानी में पुलिस विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 29 पुलिसकर्मियों की बदली तैनाती

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

रायपुर। कमिश्नरेट में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। जारी आदेश के तहत 29 अधिकारियों और कर्मचारियों की पदस्थापना बदली गई है। इसमें उपनिरीक्षक, एएसआई, प्रधान आरक्षक और आरक्षक स्तर के पुलिसकर्मी शामिल हैं। सभी को तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक अस्थायी रूप से नई जगह तैनात किया गया है। खमतराई, डीडी नगर, सिविल लाइन, आमानाका, खम्हारडीह, सरस्वती नगर, गुढ़ियारी, कोतवाली, टिकरापारा, तेलीबांधा, गंज, कबीर नगर, राजेंद्र नगर के साथ महिला थाना, यातायात, कंट्रोल रूम और रक्षित केन्द्र में बदलाव किए गए हैं।



महिला थाना और पिक गश्त में बदलाव

खमतराई थाने की ज्योति राजपूत को महिला थाना, डीडी नगर के एएसआई राधेलाल साहू को रक्षित केंद्र, पिक गश्त की

स्वलेहा शेख को आमानाका और आमानाका की सरिता यादव को पिक गश्त में भेजा गया है। रक्षित केंद्र के नागेंद्र सिंह को खमतराई, सरस्वती नगर के आंसकर केरकेट्टा को रक्षित केंद्र और खम्हारडीह के अभय गणोरकर

को यातायात में पदस्थ किया गया है।

कोतवाली, सिविल लाइन में नई तैनाती

गुढ़ियारी के सियाराम धुर्वे को रामनगर चौकी, कोतवाली की प्रीति वर्मा को महिला थाना, एसीपी कोतवाली कार्यालय के मेहतर सिंह को खम्हारडीह, सिविल लाइन के खेमराज वर्मा को एसीपी सिविल लाइन कार्यालय, महिला थाने की प्रमीला कुंजाम को कोतवाली भेजा गया है। कामता जांगड़े का डीडी नगर तबादला निरस्त कर महिला थाने में ही रखा गया है।

टिकरापारा, तेलीबांधा में फेरबदल

रक्षित केंद्र की लेखा अग्रवाल

सुरक्षा पर 150 करोड़ खर्च का दावा

मीडिया रिपोर्टों के अनुसार प्रदेश में करीब 400 नेताओं की सुरक्षा में 1550 से अधिक जवान और 500 से ज्यादा वाहन लगे हैं, जिन पर सालाना करीब 150 करोड़ रुपए खर्च होने का दावा है। जम्मू-कश्मीर के बाद छत्तीसगढ़ इस मामले में प्रमुख राज्यों में है। बस्तर में ही करीब 250 स्थानीय नेताओं को सुरक्षा मिली हुई है, जिसमें 1000 से अधिक जवान तैनात होने का दावा है।



छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

गौरेला-पेंड्रा-मरवाही। पेंड्रा-बिलासपुर मुख्य मार्ग पर पटियाला हाउस के पास उस समय हड़कंप मच गया, जब एक दुर्लभ सफेद भालू जंगल से भटककर मुख्य

मंत्री राजवाड़े के निर्देश पर 12 पर्यवेक्षकों की परिवीक्षा अवधि समाप्त

महिला एवं बाल विकास विभाग ने जारी किया आदेश

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

रायपुर। महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े के निर्देश पर विभागीय प्रक्रिया पूरी करते हुए प्रदेश के विभिन्न जिलों में पदस्थ 12 पर्यवेक्षकों की विभागीय परिवीक्षा अवधि समाप्त करने का आदेश जारी किया गया है। विभागीय समिति की 12 अक्टूबर को हुई बैठक में की गई अनुशंसा के आधार पर 22 अक्टूबर को यह आदेश जारी हुआ। परिवीक्षा अवधि पूरी करने वाले पर्यवेक्षक बस्तर, कोंडागांव, दंतेवाड़ा, बालोद, दुर्ग और रायपुर जिले में पदस्थ हैं। इनमें श्रीमती माया यादव, सुश्री अनुका चन्द्रवंशी,



सुश्री धनेश्वरी नाग, श्रीमती रितु देवांगन, सुश्री रजनी भौमना, श्रीमती संध्या साहू, श्रीमती डिम्पल साहू, श्रीमती तुषिता शर्मा, श्रीमती अंजू सिंह, सुश्री अम्बा पटेल, सुश्री गुंजा धुव और श्रीमती कंचन माहेश्वरी शामिल हैं। श्रीमती तुषिता शर्मा के मामले में विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने की तिथि के आधार पर परिवीक्षा अवधि समाप्त करने

की कार्यवाही की गई है। यह आदेश छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम 8(6) के तहत जारी किया गया है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि स्थायी पद उपलब्ध नहीं होने के कारण फिलहाल स्थायीकरण का आदेश जारी नहीं किया गया है। पद उपलब्ध होने पर नियमानुसार उन्हें स्थायी किया जाएगा।

चक्रवात अर्नब पर अमित शाह का एक्शन, सीएम से फोन पर ली हालात की जानकारी, केंद्रीय टीम करेगी नुकसान का आकलन

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

रायपुर। चक्रवाती तूफान 'अर्नब' के प्रभाव से हो रही बारिश के बीच केंद्र सरकार ने प्रभावित राज्यों की मदद के लिए कदम बढ़ाए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से फोन पर चर्चा कर हालात की जानकारी ली और हरसंभव सहायता का भरोसा दिलाया। गृह मंत्रालय ने बताया कि नुकसान के आकलन के लिए जल्द ही अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय टीम (आईएमसीटी) भेजी जाएगी। अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के साथ आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पुडुचेरी के मुख्यमंत्रियों से भी बात



की। उन्होंने एक्स पर जानकारी साझा करते हुए बताया कि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों राहत-

बचाव में लगी हैं। अर्नब का असर छत्तीसगढ़ के दक्षिण और मध्य क्षेत्र में दिख रहा है। 128 अक्टूबर से बस्तर संभाग में बारिश और तेज

हवा चल रही है, वहीं 29 अक्टूबर को रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़ और जांजगीर-चांपा में भी बारिश हुई। कुछ निचले इलाकों में जलभराव की आशंका है। आईएमसीटी टीमें प्रभावित क्षेत्रों में नुकसान और मदद की जरूरतों का आकलन करेंगी, जिसके आधार पर आगे सहायता तय होगी। टीमों के पहुंचने की तारीख अभी घोषित नहीं हुई है। इससे पहले राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति ने भी राहत शिविरों, बचाव दलों और संसाधनों की तैयारी की समीक्षा की थी। मौसम विभाग के अनुसार सिस्टम धीरे-धीरे कमजोर होगा, लेकिन सावधानी जरूरी है।

जनजातीय अंचलों में पर्यटन से खुलेंगे रोजगार के द्वार, होम-स्टे से आत्मनिर्भर बनेंगे आदिवासी परिवार

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

रायपुर। छत्तीसगढ़ के जनजातीय अंचलों में होम-स्टे और पर्यटन के जरिए रोजगार के नए अवसर खुल रहे हैं। राज्य सरकार की नई उद्योग नीति और होम-स्टे नीति के तहत बस्तर, सरगुजा, जशपुर जैसे क्षेत्रों में स्थानीय युवाओं और महिला समूहों को स्वरोजगार से जोड़ा जा रहा है। भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय के सहयोग से आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, नवा रायपुर द्वारा 28 अक्टूबर को एक दिवसीय राज्य स्तरीय उन्मुखीकरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें सरगुजा, जशपुर, कबीरधाम और बस्तर के जनजातीय हितग्राहियों को शामिल किया गया। छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल और आईआईएम रायपुर ने



तकनीकी सहयोग दिया।

संस्कृति और पर्यटन से मजबूत होगी ग्रामीण अर्थव्यवस्था

टीआरटीआई संचालक हिना अनिमेष नेताम ने कहा कि छत्तीसगढ़ की जनजातीय संस्कृति, पारंपरिक जीवनशैली और प्राकृतिक सौंदर्य पर्यटकों के लिए आकर्षण हैं। होम-स्टे से स्थानीय परिवार आर्थिक रूप से सशक्त होंगे और सांस्कृतिक

विरासत को नई पहचान मिलेगी।

तीन सत्रों में दिया गया प्रशिक्षण

पहले सत्र में पर्यटन विभाग की डॉ. शुभदा चतुर्वेदी ने होम-स्टे नीति, पंजीयन प्रक्रिया, मानकों और अनुदान की जानकारी दी। दूसरे सत्र में आईआईएम रायपुर की तौशीफ आयशा अंसारी ने स्वच्छता, अतिथि सत्कार, रखरखाव और कम संसाधन से व्यवसाय शुरू करने के टिप्स दिए।

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा एमसीबी जिले का हक और मान रहेगा सुरक्षित

एमसीबी जिले का हक कभी नहीं छीना जाएगा स्वास्थ्य मंत्री का कड़ा और स्पष्ट संदेश

छ.ग.फ़ंटलाइन
मनेंद्रगढ़ (एमसीबी) । छत्तीसगढ़ शासन लोक निर्माण विभाग द्वारा जारी हालिया आदेश के बीच, क्षेत्र की जनता के हितों की रक्षा के लिए प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री एवं मनेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र के विधायक श्यामबिहारी जायसवाल पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में यह विश्वास दिलाया है कि एमसीबी जिले का हक और अधिकार किसी भी कीमत पर छिने नहीं दिया जाएगा। जनता के विकास और उनकी क्षेत्रीय अस्मिता के लिए वे हमेशा से सदैव तत्पर रहे



हैं और आगे भी अपनी पूरी प्रतिबद्धता के साथ उड़े रहेंगे।
विभागीय आदेश और प्रशासनिक फेरबदल पर एक नजर
लोक निर्माण विभाग, मंत्रालय (महानदी भवन, नवा रायपुर

लो.नि.वि. सेतु निर्माण उपसंभाग मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर का सृजन किया गया था, जिसे प्रशासनिक प्रक्रियाओं के तहत संचालित किया जा रहा है। अधिकारियों की पदस्थापना: सेतु उपसंभाग मनेंद्रगढ़ में कार्यरत समस्त अमले को आगामी आदेश तक मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर कार्यालय हेतु ही कार्य संपादित करने के आदेश दिए गए हैं, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि स्थानीय स्तर पर विकास कार्यों और प्रशासनिक कसावट में कोई रुकावट न आए।
पारदर्शिता और त्वरित कार्रवाई:
अवर सचिव मनराखन भूआर्य के

हस्ताक्षर से जारी इस आदेश की प्रतियां प्रमुख अभियंता, कलेक्टर, और जिला कोषाधिकारी सहित तमाम संबंधित विभागों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित की जा चुकी हैं। जनता के प्रति अटूट निष्ठा स्वास्थ्य मंत्री श्यामबिहारी जायसवाल के इस मुखर और सकारात्मक रुख से मनेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र की जनता में भारी उत्साह और संतोष का माहौल है। मंत्री जायसवाल ने यह साबित कर दिया है कि उनके लिए जनता का हित सर्वोपरि है और वे अपने क्षेत्र के अधिकारों की रक्षा के लिए हर संभव कदम उठाने को तैयार हैं।

सेवा सेतु केंद्रों के संचालकों और ऑपरेटरों को मिला प्रशिक्षण



छ.ग.फ़ंटलाइन
कोरिया। आम नागरिकों को सेवा सेतु पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध सेवाओं का लाभ समय पर दिलाने के उद्देश्य से गुरुवार को जनपद पंचायत बैकुंठपुर में जिला स्तरीय एक दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया गया। इसमें जिले के सेवा सेतु केंद्रों के संचालकों एवं ऑपरेटरों को विभिन्न सेवाओं की आवेदन प्रक्रिया और समयबद्ध निराकरण की जानकारी दी गई। ई-जिला मैनेजर श्री राकेश ने बताया कि शासन के निर्देशानुसार प्रशिक्षण में कक्षा नवमी एवं बारहवीं के विद्यार्थियों को स्थानांतरण प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया बताया गया साथ ही प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने की प्रक्रिया भी समझाई गई। संचालकों और ऑपरेटरों को

बताया गया कि विद्यार्थियों के आवेदनों पर निर्धारित समय-सीमा में कार्रवाई कर प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाना है, ताकि उन्हें अनावश्यक परेशानी न हो। प्रशिक्षण के दौरान शासन की विभिन्न सेवाओं के संबंध में भी जानकारी दी गई, जिससे नागरिकों को आवश्यक दस्तावेज समय पर प्राप्त हो सकें। ईडीएम ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के

लिए जारी किए जाने वाले ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र की आवेदन प्रक्रिया के बारे में भी बताया। नए सेवा सेतु केंद्रों के संचालकों को पोर्टल के संचालन एवं सेवाओं से संबंधित जानकारी दी गई। प्रशिक्षण में आवेदकों को सही मार्गदर्शन देने, आवेदन प्रक्रिया सुगम बनाने और पात्र नागरिकों को समय पर सेवाओं का लाभ दिलाने पर जोर दिया गया।

वोट बचाओ देश बचाओ अभियान के तहत कांग्रेस ने की प्रेसवार्ता

छ.ग.फ़ंटलाइन
मनेन्द्रगढ़ (एमसीबी)। वोट बचाओ देश बचाओ कांग्रेस द्वारा राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत स्त्रुक्र के मुद्दे को लेकर बुधवार को ढुष्ट्र के पर्यवेक्षक देवाशीष पटनायक एमसीबी जिला मुख्यालय मनेंद्रगढ़ पहुंचे जहां पर उन्होंने प्रकरा भवन में प्रेसवार्ता कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर वोट चोरी करने और लोकतंत्र की हत्या करने का आरोप लगाते हुए उनसे इस्तीफे की मांग की और उन्होंने 1 नवंबर को इस मुद्दे को लेकर दिल्ली में होने वाले कांग्रेस का देश व्यापी आंदोलन के बारे में जानकारी दी। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा नियुक्त किए गए आब्जर्वर देवाशीष पटनायक ने प्रेसवार्ता में कहा कि वोट चोरी का मुद्दा केवल मौजूदा स्त्रुक्र प्रक्रिया तक सीमित नहीं है। कांग्रेस ने कई चुनावों के दौरान मतदाता सूचियों में नाम जोड़ने और हटाने, दोहरे पंजीकरण, चुनाव संबंधी आँकड़ों में पारदर्शिता, श्रृङ्खल और श्रृङ्खल की कार्यप्रणाली तथा चुनाव आयोग के आचरण पर लगातार



सवाल उठाए हैं। मूल सवाल यह है कि क्या प्रत्येक पात्र नागरिक अपने संवैधानिक मताधिकार का प्रयोग कर सकता है और क्या चुनाव एक निष्पक्ष संस्था की निगरानी में कराए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और कांग्रेस ने कथित अनियमितताओं पर सवाल उठाने के लिए बार-बार निर्वाचन क्षेत्र के स्तर के आँकड़े और चुनावी तुलनाएं सार्वजनिक की हैं। इसमें 7 फरवरी 2025 को महाराष्ट्र में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस, 7 अगस्त 2025 को महादेवपुरा से जुड़े आँकड़ों की प्रस्तुति, सितंबर 2025 में आलंद से जुड़े आरोप, नवंबर 2025 में हरियाणा से जुड़े आरोप और सितंबर 2026 में चुनाव आयोग के भीतर मतभेदों के खुलासे के

वोट बचाओ देश बचाओ अभियान को लेकर कांग्रेस की बैठक का आयोजन

मनेन्द्रगढ़ (एमसीबी)। जिला कांग्रेस कमेटी एमसीबी के द्वारा बुधवार को अहिंसा भवन, मनेंद्रगढ़ में 'वोट बचाओ - देश बचाओ अभियान' के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में एआईसीसी ऑब्जर्वर डॉ. देवाशीष पटनायक, छत्तीसगढ़ विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत, प्रभारी सचिव सुश्री जारोता लैतफलांग, सांसद श्रीमती ज्योत्सना महंत, जिला प्रभारी



उत्तम वासुदेव, जिला अध्यक्ष अशोक श्रीवास्तव, पूर्व विधायक गुलाब कमरो, पूर्व विधायक डॉ

पूर्व जिला पंचायत सदस्य शरण सिंह, सांसद प्रतिनिधि सुरेन्द्र सिंह माखोजा, पूर्व जनपद अध्यक्ष डॉ विनय शंकर सिंह, पूर्व नपा उपाध्यक्ष कृष्ण मुरारी तिवारी, रफीक मेमन, गोपाल द्विवेदी, पूनम सिंह, अकरम मंसूरी सहित काफी संख्या में जिले भर से आए कांग्रेस जनों की उपस्थिति में अभियान की रणनीति, संगठनात्मक तैयारियों और आगामी कार्ययोजना पर चर्चा की गई। इस दौरान लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा,

मताधिकार की सुरक्षा तथा संगठन को मजबूत बनाने के लिए अभियान को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने पर जोर दिया गया। बैठक में मुख्य रूप से ओम प्रकाश गुप्ता, रवि प्रताप सिंह अवधेश सिंह, युधिष्ठिर कमरो, रामनरेश पटेल, शिवांश जैन, अंकुर सिंह, जयप्रकाश साहू, मनोज शर्मा, रामय्यारे चोहान, दुपद चौहान, गिरधर जायसवाल, मोहम्मद सईद, गितिका चंदेल सहित बड़ी संख्या कांग्रेस जन उपस्थित रहे।

करण राठौर हत्या मामले में 07 आरोपियों के खिलाफ न्यायालय ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

■ **प्रकरण में एक आरोपी को न्यायालय ने किया दोषमुक्त**

छ.ग.फ़ंटलाइन
मनेंद्रगढ़ (एमसीबी) । थाना मनेंद्रगढ़ क्षेत्र में दिनांक 05.09.2025 को करण राठौर की हत्या के प्रकरण में प्रथम अपर सत्र न्यायालय मनेंद्रगढ़ द्वारा दिनांक 28.10.2026 को महत्वपूर्ण निर्णय पारित करते हुए प्रकरण के 07 आरोपियों को दोषसिद्ध कर आजीवन कारावास सहित अन्य दंड से दंडित किया गया है। प्रकरण के अनुसार दिनांक 05.09.2025 को रात्रि लगभग 10:00 बजे से 10:30 बजे के



मध्य मनेंद्रगढ़ स्थित बताशा लाइन, हनुमान मंदिर के सामने गली में आरोपियों द्वारा विध्वंस विरुद्ध जमाव बनाकर घातक हथियारों से बल एवं हिंसा का प्रयोग किया गया तथा करण राठौर पर चाकू से प्राणघातक हमला किया गया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। प्रकरण में पुलिस द्वारा विवेचना पूर्ण कर आरोपियों

103(1)/191 के अपराध में दोषसिद्ध पाया। न्यायालय द्वारा उक्त सातों दोषसिद्ध आरोपियों को बीएनएस की धारा 191(3) के तहत 02-02 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 7500-7500 के अर्थदंड तथा बीएनएस की धारा 103(1)/191 के तहत आजीवन कारावास एवं 71,000-71,000 के अर्थदंड से दंडित किया गया है। न्यायालय द्वारा दोनों सजाएं साथ-साथ चलाए जाने का आदेश दिया गया है। अर्थदंड की अदायगी नहीं किए जाने पर आदेशानुसार अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगताना जाएगा। प्रकरण में आरोपी प्रभात सोधिया उर्फ रवि के विरुद्ध बीएनएस की धारा 249 के आरोप के संबंध में न्यायालय ने अभियोजन द्वारा

आरोप को युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं पाया। फलस्वरूप न्यायालय द्वारा उसे संदेह का लाभ देते हुए उक्त आरोप से दोषमुक्त घोषित किया गया है। न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध आरोपियों पर कुल 710,500 का अर्थदंड अधिरोपित किया गया है। अर्थदंड की राशि जमा होने पर उसमें से 710,000 मृतक करण राठौर के माता अथवा पिता को प्रतिकर स्वरूप प्रदान करने तथा शेष 7500 शासन के पक्ष में जमा करने का आदेश दिया गया है। यह निर्णय गंभीर आपराधिक प्रकरणों में प्रभावी विवेचना, सलाह, संलग्न, कंचनपुर एवं बुधर में विकसित भारत जीरामजी योजनांतर्गत कराए जा रहे विकास कार्यों का जायजा लिया और

ग्रामीण विकास के निर्माण कार्यों की गुणवत्ता का ध्यान रखें एजेंसियां-योगेन्द्र श्रीवास

छ.ग.फ़ंटलाइन

कोरिया। कोरिया जिले में विकास के लिए हो रहे प्रत्येक निर्माण कार्य में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने के लिए निरंतर निगरानी की जा रही है। कलेक्टर कोरिया श्रीमती रोजिता यादव ने सभी अधिकारियों को नियमित निरीक्षण कर कार्यों की प्रगति व गुणवत्ता की जांच करने के निर्देश जारी किए गए हैं। इसी तारतम्य में बुधवार को मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री योगेन्द्र श्रीवास द्वारा जनपद बैकुंठपुर अंतर्गत कई ग्राम पंचायतों का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। अपने औचक निरीक्षण के तहत उन्होंने बैकुंठपुर जनपद अंतर्गत ग्राम पंचायत अमरपुर, सलबा, कंचनपुर एवं बुधर में विकसित भारत जीरामजी योजनांतर्गत कराए जा रहे विकास कार्यों का जायजा लिया और



संबंधितों को आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। कलेक्टर कोरिया के निर्देशन में जनपद पंचायत बैकुंठपुर के कई ग्राम पंचायतों के औचक निरीक्षण में निकले जिला पंचायत सीईओ श्री योगेन्द्र श्रीवास ने सबसे पहले ग्राम पंचायत अमरपुर पहुंचकर यहां बन रहे आंगनबाड़ी केंद्र का जायजा लिया। समय पर कार्य पूर्णता के निर्देश देने के बाद उन्होंने अमरपुर में जल संरक्षण के लिए हो रहे कंरूर

ट्रेंच कार्य का भी अवलोकन किया। अमरपुर के बाद सीईओ ने ग्राम पंचायत सलबा में बन रहे बालिका शौचालय निर्माण कार्य, ग्राम पंचायत बोड़ार के आंगनबाड़ी भवन तथा कंरूर ट्रेंच कार्य का अवलोकन किया। इसके पश्चात उन्होंने ग्राम पंचायत कंचनपुर पहुंचकर वहां विद्यालयीन परिसर में बन रहे सर्वसुविधा युक्त प्रांगितरित बालिका शौचालय निर्माण कार्य का निरीक्षण किया।

26वें राज्योत्सव में बिखरेगी छत्तीसगढ़ी संस्कृति की छटा, संजय सुरीला के लोकगीतों से सजेगी शाम

कोरिया। छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर आगामी 2 नवंबर, सोमवार को बैकुंठपुर में 26वें राज्योत्सव का आयोजन किया जाएगा। शासकीय आदर्श रामानुज उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के मिनी स्टेडियम में आयोजित समारोह में स्थानीय प्रतिभाओं के साथ प्रदेश के कलाकार सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देंगे। प्रसिद्ध लोकगायक संजय सुरीला के छत्तीसगढ़ी लोकगीत कार्यक्रम का विशेष आकर्षण होंगे। समारोह के शुभांश अवसर पर बैकुंठपुर विधायक श्री भईया लाल राजवाड़े मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, सायं 4 से 5:30 बजे तक स्थानीय कलाकार अपनी प्रतिभा का

प्रदर्शन करेंगे। सायं 5रू30 से 6 बजे तक मुख्य अतिथि का आगमन एवं उद्घाटन कार्यक्रम होगा। इसके बाद सायं 6 से रात्रि 10 बजे तक विशेष सांस्कृतिक प्रस्तुतियां होंगी। सांस्कृतिक संस्था में अंबिकापुर के संजय सुरीला छत्तीसगढ़ी लोकगीतों की प्रस्तुति देंगे। बिलासपुर के वाइब्रेशन डॉस स्टूडियो की वेस्टर्न डॉस प्रस्तुति भी आकर्षण का केंद्र होगी। नरेंद्र जलक्षेत्रिय एवं सुश्री शिल्पा सिंह कथक नृत्य, निनवा का जय दुर्गा पंडवानी दल पंडवानी तथा रायपुर का सियाधेश म्यूजिक सुगम संगीत की प्रस्तुति देगा। कलेक्टर श्रीमती रोजिता यादव ने बताया कि राज्योत्सव की तैयारियों को लेकर अधिकारियों को लगातार दिशा-निर्देश दिए जा रहे हैं।

राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार के लिए ग्राम पंचायत घुटरा का केंद्रीय टीम ने किया निरीक्षण

‘बाल हितैषी पंचायत’ थीम में नामांकन, पंचायत भवन, आंगनवाड़ी, उप स्वास्थ्य केंद्र एवं विद्यालयों के अभिलेखों का किया सत्यापन

छ.ग.फ़ंटलाइन
मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी। जिला मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर के जनपद पंचायत मनेन्द्रगढ़ अंतर्गत ग्राम पंचायत घुटरा का राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार वर्ष 2023-24 के तहत ‘बाल हितैषी पंचायत’ थीम में नामांकन हुआ है। इसी क्रम में पंचायती राज मंत्रालय, नई दिल्ली के सीनियर पीपीएस सुरेंद्र कुमार शर्मा एवं राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान (एनआईआरडी), हैदराबाद की कंसल्टंट श्रीमती निशा बारी परनामी की संयुक्त टीम ने ग्राम पंचायत घुटरा पहुंचकर विभिन्न संस्थानों का भौतिक निरीक्षण एवं दस्तावेजों का सत्यापन किया। निरीक्षण के



दौरान केंद्रीय टीम ने ग्राम पंचायत भवन, आंगनवाड़ी केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र एवं विद्यालयों में संधारित अभिलेखों का अवलोकन कर संबंधित व्यवस्थाओं की जानकारी ली। टीम ने बाल हितैषी

पंचायत थीम के अंतर्गत बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण एवं उनके समग्र विकास से जुड़ी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। साथ ही पंचायत स्तर पर संचालित गतिविधियों एवं उपलब्ध सुविधाओं की समीक्षा

की। इस अवसर पर जनपद पंचायत मनेन्द्रगढ़ की मुख्य कार्यपालन अधिकारी सुश्री वैशाली सिंह, जनपद पंचायत के अधिकारी-कर्मचारी, ग्राम पंचायत के सरपंच, पंच, सचिव, रोजगार

सहायक, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, ग्रामीणजन उपस्थित रहे। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार के लिए ग्राम पंचायत घुटरा का नामांकन जिले के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है। यह

निरीक्षण पुरस्कार की मूल्यांकन प्रक्रिया का हिस्सा है, जिसके माध्यम से पंचायत स्तर पर बच्चों के हित में किए जा रहे कार्यों एवं उपलब्ध व्यवस्थाओं का सत्यापन किया जा रहा है।